सांध्य दैनिक

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./ दुर्ग /94/2023-25

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 16 अंक - 216 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, मंगलवार 20 मई 2025 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

समय से पहले केरल में दस्तक दे सकता है मानसून
अगले 4-5 दिनों में मिल सकती है खुशखबरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दक्षिण-पश्चिम मानसून तय अनुमानित समय से पहले केरल में दस्तक दे सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के अगले चार-पांच दिनों में केरल पहुंचने की संभावना है। यह 1 जून की सामान्य तिथि से काफी पहले है। मौसम विभाग ने पहले पूर्वानुमान लगाया था कि मानसून 27 मई तक केरल में दस्तक देगा। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, अगर मानसून उम्मीद के मुताबिक केरल पहुंचता है तो यह 2009 के बाद से सबसे जल्दी दस्तक देगा। तब यह 23 मई को शुरू हुआ था।

आईएमडी ने मंगलवार दोपहर को एक अपडेट में बताया कि अगले 4-5 दिनों के दौरान केरल में मानसून के दस्तक देने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। आम तौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक देता है। इसके बाद 8 जुलाई तक यह पूरे देश को कवर कर लेता है। यह 17 सितंबर के आसपास उत्तर-पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू करता है और 15 अक्तूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है।

पूर्व में स्वीकृत राशि से ही बनेगा स्काईवॉक

भ्रष्टाचार हुआ तो कार्रवाई क्यों नहीं की?-मूणत

■ राजेश मूणत ने कहा- कांग्रेस ने पांच साल में विकास नहीं केवल भ्रष्टाचार किया

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री और रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने राजधानी रायपुर के ड्रीम प्रोजेक्ट स्काई-वॉक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्काई वॉक के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं है। पूर्व में स्वीकृत राशि से ही इसे बनाया जायेगा। इस मामले में कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस शासनकाल में हुई राजनीति और अड़ंगेबाजी पर कांग्रेस पर जमकर तीखा हमला बोला है। मूणत ने आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश सरकार में विकास नहीं केवल भ्रष्टाचार किया गया। उसके पास विकास का विजन ही नहीं है।

इस निर्माण कार्य को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति के रूप में 37 करोड़ रुपए आवंटन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री/लोक निर्माण मंत्री अरुण साव का आभार जताया है। भाजपा विधायक कहा कि डेवलपमेंट विजन के साथ स्काई वॉक निर्माण कार्य डॉ. रमन सिंह के के मुख्यमंत्रित्व काल में सरकार की प्रक्रियाओं का शत-प्रतिशत पालन किया गया था। 2016-17 में बजट में प्रावधान करके शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक और शास्त्री चौक से जेल तिराहे तक जो लोग पैदल चलते हैं, उसके कारण ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है, उस दृष्टि से अध्ययन करने के उपरांत 2016-17 में बजट में इसका प्रावधान किया गया। सरकार ने उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। उसी वर्ष प्रशासनिक एजेंसी ने सर्वे करने के लिए एजेंसी का टेंडर आमंत्रित किया, जिसमें दो एजेंसी ने भागीदारी की। स्काई वॉक की उपयोगिता और आवश्यकता पर डिटेल सर्वे आया।

तब कांग्रेस ने नहीं उठाया सवाल

उन्होंने कहा कि सर्वे आने के बाद इसके तीन प्रेजेंटेशन इस रायपुर शहर के अंदर हुए, जिसमें नगर निगम के उस समय की महापौर डॉ. किरणमयी नायक, सत्यनारायण शर्मा, प्रमोद दुबे, निगम कमिश्नर, कलेक्टर, यातायात विभाग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सब लोगों ने संयुक्त रूप से इस प्रेजेंटेशन को देखा और सब लोगों ने अपने सुझाव के अनुसार उसमें सुझाव भी दिए। उन सुझावों का समावेश करने के उपरांत फाइनल इस्टीमेट बनाकर राज्य सरकार को टेंडर की प्रक्रिया और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया। पीडब्ल्यूडी की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के उपरांत टेंडर हुआ। साल 2017 में यह काम चालू हुआ। जिस दिन उसका भूमिपूजन हुआ, उस दिन रायपुर के समाचार पत्रों में विज्ञापन के साथ-साथ पूरी डिटेल जनता के बीच रखी गई। विधानसभा में कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कोई सवाल नहीं उठाया। कभी कोई बात नहीं की।

मूणत ने कहा कि जब स्काई वॉक का काम शुरू हुआ था तब स्मार्ट सिटी योजना शुरू नहीं हुई थी। भाजपा की हमारी तत्कालीन सरकार ने पहले उन योजनाओं पर भी काम किया ताकि सड़क आवागमन सुविधाजनक हो, ट्रैफिक जाम की स्थिति न हो। स्काई व़ॉक के साथ जुड़ी विभिन्न सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए मूणत ने कहा कि 2018 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि स्काई वॉक नहीं बनना चाहिए। हालाँकि इसका कोई आधिकारिक आदेश संबंधित विभाग ने नहीं निकाला था।

तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तीन स्तरों पर कराई जाँच

तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तीन स्तरों पर इसकी जाँच कराई। तमाम जाँच प्रक्रियाओं के बाद यह निष्कर्ष निकला कि राजधानी की आवश्यकता और इस काम में खर्च हो चुकी राशि को देखते हुए इस स्काई व़ॉक को पूर्ण करना चाहिए, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल व कांग्रेस नेताओं ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया। स्काई वॉक को लेकर कांग्रेस सरकार के रवैये पर तंज कसते हुए कहा कि बाद में फिर से हुई जाँच की रिपोर्ट में इस योजना को क्लीन चिट देते हुए कहा गया कि इस काम में कहीं भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर स्काई वॉक में कोई भ्रष्टाचार हुआ तो इससे संबंधित फाइल, अधिकारी तत्कालीन भूपेश सरकार के पास थे तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? पत्रकार वार्ता में प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल, जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, सोशल मीडिया सह प्रभारी मितुल कोठारी मौजूद रहे।

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: सिविल जज बनने के लिए तीन साल बतौर वकील प्रैक्टिस जरूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सिविल जज जूनियर डिविजन के पद के लिए उम्मीदवार अब सीधे परीक्षा पास कर नियुक्त नहीं हो सकेंगे और उन्हें तीन साल कम से कम बतौर वकील प्रैक्टिस करना जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि 'देखा गया है कि जो नए कानून स्नातक न्यायपालिका में नियुक्त होते हैं, उनके चलते कई समस्याएं हुई हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को न्यायपालिका में दाखिल होने के लिए कम से कम तीन साल बतौर वकील प्रैक्टिस करना जरूरी होगा।'

दिखाना होगा सर्टिफिकेट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रैक्टिस की अवधि नामांकन की तारीख से मानी जा सकती है। अदालत ने साफकिया कि यह आदेश उच्च न्यायालयों में हो चुकी नियुक्तियों पर लागू नहीं होगा और भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में ही ये शर्त लागू होगी। शर्त पूरी करने के लिए उम्मीदवार को 10 साल तक प्रैक्टिस कर चुके वरिष्ठ वकील या तय न्यायिक अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट को दिखाना होगा। अगर कोई वकील सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में 10 साल तक प्रैक्टिस कर चुके वकील या तय न्यायिक अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

अदालती कामकाज का अनुभव मिलना जरूरी

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देश की न्यायिक व्यवस्था पर दूरगामी असर पड़ेगा। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि न्यायिक व्यवस्था में आने से पहले अदालत का अनुभव मिलना बेहद जरूरी है। सीजेआई ने कहा कि 'कई उच्च न्यायालयों ने अनुभव किया है कि युवा कानून स्नातकों को न्यायिक पदों पर नियुक्त करने से कई समस्याएं होती हैं। अदालत के कामकाज का प्रैक्टिकल अनुभव न्यायिक व्यवस्था की दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।' सुप्रीम कोर्ट ने 'ऑल इंडिया जज एसोसिएशन' की याचिका पर यह फैसला सुनाया।

सीएम के कड़े तेवर- लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज, इन दो जिलों में हुई कड़ी कार्रवाई

मुंगेली में कार्यपालन अभियंता को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित, जिला शिक्षा अधिकारी भी नपे

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए दो बड़े निर्णय लिए। मुख्यमंत्री ने मुंगेली जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता आर.के. मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मनियारी जलाशय और पथरिया जलाशय जैसी महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हैं, जो लापरवाही का स्पष्ट प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री साय ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के जिला शिक्षा अधिकारी जगदीश कुमार शास्त्री को पद से हटाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में जिले का अत्यंत खराब प्रदर्शन जिले में शिक्षा व्यवस्था की गंभीर खामी को दर्शाता है और ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री साय के इस तीखे रुख से स्पष्ट है कि सरकारी कार्यों में शिथिलता और जवाबदेही से बचने का युग समाप्त हो चुका है।

छत्तीसगढ़ में बदला हुआ है मौसम का मिजाज बारिश और तूफान की गतिविधि बढ़ने की संभावना

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ाने के लिए परिस्थितियों अनुकूल हैं। आज 20 मई से प्रदेश में बारिश, बिजली और तेज हवा के साथ मध्यम से तीव्र तूफान के गतिविधि बढ़ जाएगी। इस दौरान कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना जताई जा रही है।

प्रदेश के अगले दो-तीन दिनों के दौरान दक्षिण अरब सागर के कुछ और हिस्सों, मालदीव और कोमॉरिन क्षेत्र के शेष हिस्सों, दक्षिण बंगाल के खाड़ी के कुछ और हिस्सों, मध्य बंगाल के खाड़ी के कुछ और हिस्सों साथ ही उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ाने के लिए परिस्थितियों अनुकूल हैं। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम-मध्य खड़ी और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवर्ती परिसंचरण बना हुआ है। यह औसत समुद्र तल से 1.5 और 5.8 की ऊपर ऊपर दक्षिण पश्चिम की ओर झुका हुआ है, और ऊंचाई बनी हुई है। इसके प्रभाव से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के एक दो जगह पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं एक दो जगह पर गरज-चमक के साथ तेज हवा 40-50 किमी की रफ्तार से चलने की संभावना है।

राजधानी रायपुर में आज मौसम बादल छाए रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के एक-दो जगह पर हल्की मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं सबसे गर्म इलाका रायपुर रहा है। यहां सर्वाधिक अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान पेण्ड्रा रोड में 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

पाकिस्तान को अपना बजट भी खुद तैयार करने का अधिकार नहीं, IMF की टीम बैठेगी

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान को लंबी जद्दोजहद के बाद आईएमएफ से एक अरब डॉलर का लोन मिलना तय हुआ है। लंबे समय से पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी संस्थाओं और चीन जैसे देशों से कर्ज के सहारे ही चल रहा है। कई बार सऊदी अरब से भी उसे सस्ता तेल और आर्थिक मदद मिलती रही है। लेकिन इसकी एवज में उसकी संप्रभुता लगातार कम होती जा रही है। यहां तक कि वह अपने देश का बजट भी खुद तय नहीं कर सकता। 2 जून को पाकिस्तान की ओर से देश का बजट पेश करने की तैयारी है और उससे पहले आईएमएफके साथ वह सलाह-मशविरा करेगा और तभी उसके प्रस्ताव तय किए जाएंगे।

राखी का बंधन हुआ शर्मसार: दो साल तक करता रहा दुष्कर्म, गर्भवती हुई तो कराया गर्भपात

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोंडागांव। कोंडागांव जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने सगे भाई पर दो साल तक लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार दो साल से उसका बड़ा भाई उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई, जिसके बाद आरोपी ने जबरन उसका गर्भपात करवाया। भाई की धमकियों के चलते वह लंबे समय तक चुप रही, लेकिन लगातार अत्याचार और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार वह घर से भाग गई। पांच दिन तक लापता रहने के बाद पीड़िता ने साहस जुटाकर सिटी कोतवाली कोंडागांव पहुंचकर पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी सौरभ उपाध्याय के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही है।

यह मामला समाज और कानून व्यवस्था दोनों के लिए चेतावनी है कि ऐसे अपराधों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई हो, ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

कहां है समान नागरिक संहिता?

श्रीकंचनपथ

मध्यप्रदेश भाजपा का एक मंत्री सेना की एक अधिकारी को आतंकवादियों की बहन बताता है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता। फिर हाईकोर्ट मामले का स्वत: संज्ञान लेता है और पुलिस एक लचर सी एफआईआर दर्ज करती है। हाईकोर्ट को इसके बाद सख्ती करनी पड़ती है। आरोपी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है जहां उसका माफीनामा तो कबूल नहीं होता पर उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एसआईटी जांच होगी। सवाल यह है कि यदि राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी भी दूसरे नेता ने यही बात कही होती तो क्या होता? वह पेड सोशल मीडिया पर ट्रोल होता। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। उसकी सांसदी या विधायकी चली जाती। मंत्री होता तो पद चला जाता। पुलिस गिरफ्तार करने के लिए घर तक चली आती। ऐसे कई मामलों में हमने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को नेस्तनाबूद होते देखा है। दरअसल, देश में दो तरह के लोग रहते हैं। एक जिनमें फालतू की बातों में यकीन करने और अपनी भक्ति सिद्ध करने की जिद है और दूसरे वो जिनकी अंतरात्मा अभी मरी नहीं है। उनमें सोचने-समझने की शक्ति थी और वे उसे अभिव्यक्त भी करते थे। ऐसे लोगों पर अब फोकटिया बुद्धिजीवी का टैग लग गया है। जिस देश को कथित तौर पर अपने गौरवशाली अतीत, संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान पर गर्व है, उसे अब तर्कशील लोग नहीं चाहिए। भाजपा के मंत्री शाह ने 11 मई को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था, 'उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते। इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा, कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है, तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान-सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ले सकते हैं।' जाहिर है कि वो आतंकवादियों को पाकिस्तान से नहीं बल्कि मुसलमानों से जोड़ कर देख रहे थे। बावजूद इसके मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार और वहां की पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। जब पूरा देश एकजुट होने का संदेश दे रहा था तब वह हिन्दू मुसलमान कार्ड खेल रहा था। शाह के माफी मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि कभी-कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है, तो कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है।

आपने भद्दे कमेंट किये, अब आपकी माफी का क्या मतलब? बदतमीजी और हल्की बातों का शाह से पुराना नाता रहा है। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी से लेकर राहुल गांधी तक के खिलाफ वह बकवास करता रहा है। इसके बाद भी न केवल वह पार्टी में है, बल्कि पार्टी टिकट पर विधायक भी है और मंत्री भी। यही तो है संस्कार और संस्कृति का दोगलापन।

संपादकीय

कहने का मौका क्यों दिया जाए कांग्रेस को

राजनीति में नेता,मंत्री व सरकार की कोशिश होती है कि विरोधी दल को कुछ कहने का मौका क्यों दिया जाए, खासकर किसी अधूरे काम को लेकर। विरोधी दल तो अधूरा काम पूरा करने पर इसे पैसों की बरबादी कहेगा और पूरा नहीं करने पर कहेगा कि दो दो बार सरकार बनने के बाद भी भाजपा एक अधूरा काम पूरा नहीं करा सकी। अक्सर जब भी कोई चुनाव आता है तो याद किया जाता है कि किस दल ने क्या काम कराने को कहा था और पूरा नहीं कराया, किस सरकार के समय का कौन सा काम अधूरा है और उसे पूरा क्यों कराया जा रहा है। काम पूरा हो जाता है इसका श्रेय विधायक, मंत्री व सरकार को जाता है कि इसने एक कार्यकाल में कोई काम पूरा नहीं करा सके तो दूसरे कार्यकाल में उसे पूरा कराया। यानी भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है।

> *ऐसा ही एक काम था रमन सिंह के समय किया गया बकाया बोनस का वादा। इसकी याद कांग्रेस नेता याद दिलाया करते थे। इसके आधार पर कांग्रेस कहा करती थी कि भाजपा ने एक वादा पूरा नहीं किया। इसलिए जब भाजपा की सरकार दोबारा बनी तो किसानों को बकाया बोनस तीन हजार करोड़ से ज्यादा दिया गया और भाजपा पर लगे वादाखिलाफी के लगे दाग को मिटा दिया गया था। तीन हजार करोड खर्च हुए तो क्या भाजपा का वादा तो पूरा हुआ, भाजपा का दाग तो मिट गया। स्काई वाक भी रमन सरकार के समय की महत्वाकांक्षी योजना थी। क्योंकि यह बन जाता तो इसे रमन सरकार की एक उपलब्धि के रूप में देखा जाता। स्काई वाक 17 में शुरू हुआ और भूपेश सरकार के आने के बाद इस पर रोक लगा दी गई।*

भूपेश सरकार ने इसे बेकार का खर्च मानकर इसे जस का तस रहने दिया। न इसे बनवाया और न ही इसे तुडवाया। क्योंकि दोनों हालत मे पैसा खर्च होता और भूपेश सरकार भाजपा सरकार की योजना पर कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी। वह इसे पूरा कराती तो इसका श्रेय भाजपा ले जाती, इसे पूरा नहीं कराती तो भी भाजपा आलोचना करती। रायपुर के अधूरे स्काईवाक को पूरा कराने के लिए पांच साल बाद सही आदेश व पैसा जारी होने के बाद भाजपा व कांग्रेस में इसे लेकर राजनीति फिर शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा व पूर्व मंत्री राजेश मूणत पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह स्काई वाक नही कमीशन वाक है। उनका कहना है कि शहर में पैदल चलने वालों की संख्या कम होती जा रही है, ऐसे में शहर की जरूरत स्काईवाक नहीं फ्लाईओवर है।

कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि पूर्व मंत्री मूणत कितनी भी गलतबयानी कर लें रायपुर का एक्सप्रेस वे, स्काईवाक भाजपा के भ्रष्टाचार के स्मारक के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता के सामने खड़ा है। राजेश मूणत ने इस मामले में कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा है कि स्काई वाक की लागत बढ़ी है तो इसके लिए कांग्रेस दोषी है। कई कमेटियों ने भूपेश सरकार को स्काईवाक को पूरा कराने की रिपोर्ट दी थी लेकिन भूपेश सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में शहर के यातायात के सुगम बनाने के लिए स्काईवाक के निर्माण की योजना बनाई गई थी। तब महसूस किया गया था कि शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक,शास्त्री चौक से जेल तिराहे तक लोग पैदल चलते है, इसके कारण यातायात बाधित होता है, तेज रफ्तार वाहनो के कारण हादसे का अंदेशा बना रहता है। इसलिए सर्वे कराया गया और तब के महापौर,पूर्व महापौर किरणमयी नायक, रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा ने सुझाव दिए थे। 2017 में इसका निर्माण शुरू हुआ।

सरकार बदल गई तो इसका काम रोक दिया गया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोप में राजेश मूणत ने कहा है कि पांच साल भूपेश बघेल की सरकार थी,उसने जांच क्यों नहीं कराई। भाजपा सरकार ने स्काई वाक बनाने के लिए 37 करोड़ रुपए स्वीकृत किए है, बताया जाता है कि 70 करोड़ पहले खर्च हो चुका है यानी स्काईवाक का कुल खर्च 100 करोड़ हो जाएगा। कुछ लोग तो यह सवाल उठा रहे है कि ठीक है 16 में इसकी जरूरत थी लेकिन आज इसके बनने के बाद इस पर चलेगा कौन, क्योंकि शहर का यातायात तो पिछले दस साल में बहुत बदल गया है। यातायात की समस्या और गंभीर हो गई है। कुछ लोगों को कहना है कि स्काईवाक में एस्केलेटर और लिफ्ट लगाए जाने है। जहां भी एस्केलेटर व लिफ्ट लगाए जाते हैं, उसकी देखभाल व मरम्मत की जरूरत भी होती है।

सवाल यह भी उठाया गया है कि कंपनी ठीक है एक बार बना देगी, तीन साल तक मेंटेन कर देगी उसके बाद इसकी देखभाल कौन सा विभाग करेगा। राजेश मूणत व भाजपा सरकार के समय का अधूरा काम है, इसे पूरा कराने में कोई ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है लेकिन बाद में इसके रखरखाव में तो बड़ा खर्च नियमित होना ही है। हमारी सरकारे व निकाय कोई काम एक बार तो करा देते हैं, उसके बाद जब उसके मेंटेनेंस की बारी आती है तो कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि इसमें पैसा खर्च होता है। जैसे रायपुर शहर के गार्डन में ओपन जिम के लिए उपकरण लगाए गए लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। ओपन जिम के उपकरण टूट गए और करोड़ो खर्च कर बनाए गए ओपन जिम किसी काम के नहीं हैं।

इसी तरह स्मार्ट सिटी के नाम वाटर एटीएम, स्मार्ट शौचालय बनाए गए लेकिन बाद में मेंटेनेंस न होने के कारण बेकार हो गए। शहर में बहुत से काम ऐसे हुए है एक बार उसके लिए पैसा खर्च कर दिया जाता है लेकिन बाद में उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।कई सौ करोड़ रुपए इसी तरह बरबाद कर दिए गए हैं। अभी स्काईवाक बना नहीं है, इसके बनने के पहले की यह तय हो जाए तो अच्छा की कि कुछ साल बाद इसकी देखरेख कौन सा विभाग करेगा, सरकार करेगी या निगम करेगा। नहीं तो तीन साल बाद पता चलेगा कि सौ करोड़ का खर्च बेकार किया गया। इसका फायदा ज्यादा समय लोगों नहीं मिला।

कमीशनखोरी का आरोप राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगाते रहते हैं और कमीशनखोरी कड़वी सचाई है। जहां भी बड़ा काम होता है तो वह कराया ही इसलिए जाता है कि उसमें पैसा कई लोगों को मिलना रहता है। जितना बड़ा काम होता है, उतनी ज्यादा कमीशनखोरी होती है। बुरी बात यह है कि अपनी कमीशनखोरी के लिए ऐसे ऐसे काम कराये जाते हैं जो कुछ समय तक लोगों के काम आते है, उसके बाद सरकारी विभाग व निकाय के लिए बोझ हो जाते हैं। हर साल जनता की सुविधा के नाम पर करोड़ो रुपए खर्च किए जाते हैं लेकिन जनता को उसका लाभ लंबे समय तक नहीं मिलता है। शान से बताया तो जाता है कि हमारे समय में जनता के लिए क्या क्या किया गयाल लेकिन कोई यह नहीं बताता है जो किया गया था वह कितने समय तक चला।

जीईएम - सार्वजनिक खरीद को आकर्षक बनाने का सार्थक प्रयास

पीयूष गोयल

सार्वजनिक खरीद के लिए पारदर्शी, समावेशी एवं कुशल मंच प्रदान करने के एक अग्रणी उपाय के रूप में, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पूरी दुनिया में तेजी से उभरा है। यह प्लेटफॉर्म 1.6 लाख से अधिक सरकारी खरीदारों को 23 लाख विक्रेताओं एवं सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण का एक प्रमुख वाहक बन गया है।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस परिवर्तनकारी डिजिटल पहल को शुरू किए जाने के बाद से नौ वर्षों के दौरान, जीईएम ने भ्रष्टाचार को खत्म करके और स्टार्टअप, एमएसएमई, महिलाओं एवं छोटे शहरों के व्यवसायों को व्यावसायिक अवसर प्रदान करके सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है।

उपयोगकर्ताओं के अनुकूल माना जाने वाला यह प्लेटफॉर्म एक ऐसा सच्चा रत्न है, जिसने कुख्यात आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डायरेक्टरेट जनरल ऑफसप्लाइज एंड डिस्पोजल्स) की जगह ले ली है। इस महानिदेशालय की अपारदर्शी और गैर-प्रतिस्पर्धी प्रणालियां कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को अनुचित लाभ प्रदान करती थीं। इसलिए यह उचित ही है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का नया कार्यालय, वाणिज्य भवन, उस भूमि पर बनाया गया है जिस पर कभी यह पुराना निकाय स्थित था।

शानदार प्रगति-वर्ष 2016 में स्थापना के बाद से, जीईएम पोर्टल पर 13.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर का लेन-देन किया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान, इस प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक खरीद बढ़कर रिकॉर्ड 5.43 लाख करोड़ रुपये की हो गई। जीईएम का लक्ष्य वर्तमान वित्त वर्ष में अपने वार्षिक कारोबार को बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपये करना है। जीईएम निस्संदेह सार्वजनिक खरीद से जुड़े परिदृश्य में एक असाधारण तकनीकी उपाय के रूप में उभरा है।

कारोबार के आकार की दृष्टि से, जीईएम निकट भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक खरीद पोर्टल बन जाएगा और दक्षिण कोरिया के कोनेप्स जैसी सुप्रतिष्ठित संस्थाओं को पीछे छोड़ देगा।

जीईएम ने ईमानदारी से व्यावसाय करने प्रतिष्ठानों को व्यापक अवसर प्रदान किए हैं, नौकरियां सृजित की हैं और भारत के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है। इस संदर्भ में, जीईएम का महत्व वित्तीय दृष्टि से इसकी अभूतपूर्व प्रगति से कहीं बढ़कर है जो अपने आप में ई-कॉमर्स से जुड़ी किसी भी बड़ी कंपनी को हैरान कर देने के लिए काफी है।

न्यायसंगत विकास का वाहक - जीईएम प्रधानमंत्री मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' मिशन के अनुरूप न्यायसंगत विकास के एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में कार्य करता है। यह स्टार्टअप, छोटे व्यवसायों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बिना किसी बिचौलियों के सरकारी खरीदारों के सामने अपने उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदर्शित करने का एक आसान रास्ता प्रदान करता है। प्रवेश की सभी बाधाओं को दूर करके, यह प्लेटफॉर्म छोटे घरेलू व्यवसायों को ई-टेंडर में भाग लेने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने का अधिकार देता है।

समावेशिता के सिद्धांत से प्रेरित, जीईएम ने छोटे व्यवसायों के विकास को समर्थन देने के उद्देश्य से विभिन्न रणनीतिक पहलों का समावेश किया है। इनमें सरकारी खरीदारों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों एवं सेवाओं की पहचान करने तथा उनका चयन करने में मदद करने वाली प्रणालियां शामिल हैं।

लक्ष्य से आगे - जीईएम पर स्टार्टअप रनवे और वुमनिया जैसे समर्पित स्टोरफ्रंट ने इन व्यवसायों की दृश्यता के साथ-साथ सार्वजनिक खरीद में उनकी हिस्सेदारी को भी प्रभावी ढंग से बढ़ाया है। इससे सरकार को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से 25 प्रतिशत खरीद और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों से 3 प्रतिशत खरीद के अपने लक्ष्यों को पूरा करने और उससे आगे निकलने में मदद मिली है। जीईएम पर किए गए कुल कारोबार का लगभग 38 प्रतिशत हिस्सा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को दिया गया है और महिला उद्यमों द्वारा खरीद की हिस्सेदारी लगभग 4 प्रतिशत है।

अप्रैल 2025 तक 30,000 से अधिक स्टार्टअप ने जीईएम के जरिए 38,500 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है। इसके अलावा, 1.81 लाख उद्यम-सत्यापित महिला उद्यमियों ने जीईएम पोर्टल पर लगभग 50,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर हासिल किए हैं।

बड़ी बचत - इन बदलावों से कुछ खास आकार के ऑर्डरों के लिए 33 प्रतिशत से लेकर 96 प्रतिशत तक की बचत हुई है। यह उल्लेखनीय कमी देश के आम नागरिकों के हित में व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) और जीवन-यापन में आसानी (ईज ऑफ लिविंग) को बढ़ाने के मोदी सरकार के मिशन के अनुरूप एक स्वागत योग्य बदलाव है।

विश्व बैंक द्वारा किए गए एक स्वतंत्र मूल्यांकन से यह पता चला है कि जीईएम पर खरीदार औसत कीमत पर लगभग 9.75 प्रतिशत की बचत करते हैं। इससे करदाताओं के पैसे का उपयोग करके की जाने वाली सार्वजनिक खरीद में अनुमानित रूप से 1,15,000 करोड़ रुपये की भारी बचत हुई है। जीईएम पर खरीद ने सरकारी कंपनी एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपये के अनुबंध में रिवर्स नीलामी का उपयोग करके 2,000 करोड़ रुपये बचाने में मदद की। जीईएम ने रक्षा उपकरणों, टीकों, ड्रोन और बीमा जैसी सेवाओं की पारदर्शी एवं किफायती खरीद में भी मदद की है।

छोटे उद्यमों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए, जीईएम ने हाल ही में अपने लेनदेन शुल्क में उल्लेखनीय कमी की है। 10 लाख रुपये से अधिक के ऑर्डर पर 0.30 प्रतिशत का कम लेनदेन शुल्क लगेगा, जबकि 10 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर पर 3 लाख रुपये का सीमित शुल्क लगेगा - जोकि पहले के 72.50 लाख रुपये के शुल्क से काफी कम है।

प्रौद्योगिकी, एआई - एक ठोस तकनीकी बुनियादी ढांचे से लैस, यह प्लेटफॉर्म विभिन्न तकनीकी उपायों का उपयोग करके व्यापार करने के नए एवं आसान तरीके पेश करते हुए लगातार विकसित होता जा रहा है। जीईएम ने जीईएम एआई नामक एक एआई-संचालित चैटबॉट का समावेश किया है - यह संवादात्मक विश्लेषण और व्यावसायिक बुद्धिमत्ता में प्रशिक्षित एक उपकरण है। यह स्मार्ट चैटबॉट आठ स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है और जीईएम पोर्टल पर व्यापार करने में आसानी को और बढ़ाने के लिए वॉयस कमांड कार्यक्षमता सहित नवीनतम तकनीकों से लैस है।

जीईएम सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) विक्रेताओं के लिए वित्तपोषण संबंधी उत्पाद भी प्रदान करता है। यह पात्र खरीद आर्डरों के लिए 10 मिनट से भी कम समय में गिरवी-मुक्त वित्तपोषण प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म ने जीईएम सहाय 2.0 पेश किया है, जो 10 लाख रुपये तक के ऋण को हासिल करने के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करता है। इस प्लेटफॉर्म को और अधिक समावेशी एवं प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु पहले की अपेक्षा अधिक पहलों एवं तकनीकी उपायों पर काम चल रहा है।

जीईएम पोर्टल भारत के आर्थिक विकास और प्रधानमंत्री मोदी के प्रगति संबंधी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाले एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में सक्रिय है। यह समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाने एवं उनका उत्थान करने तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए हमेशा अतिरिक्त प्रयास करेगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि करदाताओं के पैसे का कुशलतापूर्वक उपयोग प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की खरीद के लिए किया जाए।

ऑपरेशन सिंदूर: राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान का संगम

सुश्री लक्ष्मी पुरी, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महिला की उप कार्यकारी निदेशक तथा भारत की पूर्व राजदूत।

ऑपरेशन सिंदूर ने स्पष्ट किया है कि भारत वैधता नहीं चाहता है। देश न्याय चाहता है। भारतीय संयम को कभी भी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी कृत्य के प्रति भारत की जवाबी प्रतिक्रिया - ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी भी जारी है- आतंकवाद-रोधी और सैन्य सिद्धांत तथा रुख में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। अपने जोशीले भाषण में, जिसकी गूंज पूरे भारत और दुनिया के विभिन्न देशों की राजधानियों में सुनायी दी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि सीमा-पार आतंकवाद के किसी भी कृत्य के खिलाफ निर्णायक सैन्य कार्रवाई की एक नई सामान्य स्थिति स्थापित की गई है।

कोई भी देश, जो आतंकवादी अवसंरचना को पनाह देता है, उसे वित्तीय मदद देता है और उसका पोषण करता है, उसे अपने सैन्य बलों के साथ जोड़ता है और निर्दोष नागरिकों के खिलाफ क्रूर हमलों के लिए भारत को निशाना बनाता है, उसे त्वरित, दंडात्मक और प्रतिशोधी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। सोची-समझी सैन्य कार्रवाई से न केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बीच में भी आतंकवादी नेटवर्क ध्वस्त हो जाएंगे, भले ही राज्य प्रायोजित आतंकवादी ठिकाने आधिकारिक सुरक्षा संरचनाओं के साथ कितने भी जुड़े हुए हों।

सिंदूर सिद्धांत, भारत की संप्रभुता और सभ्यतागत लोकाचार को बनाए रखने में निहित है। इसका उद्देश्य इसकी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, आंतरिक एकता, सद्भाव और शांति सुनिश्चित करना और 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए देश को त्वरित आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है। यह सीमा-पार आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता के रुख की पुष्टि करता है और भारत को अपने सुरक्षा हितों की रक्षा में निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध करता है, जिसे पुनर्परिभाषित और विस्तृत किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है: भारत के खिलाफ़ किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जायेगी - अब कोई संदेह की स्थिति नहीं है, किसी दूसरे तरीके से युद्ध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकवाद से होने वाले नुकसान के आगे हार नहीं मानी जाएगी। ऑपरेशन के बाद राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रधानमंत्री का संबोधन सफलता की पुष्टि से कहीं अधिक था। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर दिए गए इस संबोधन ने एक नई रणनीतिक व्यवस्था का अनावरण किया- दृढ़, गरिमापूर्ण और भारत के सभ्यतागत मूल्यों पर आधारित।

इसने एक सरल लेकिन दृढ़ संदेश दिया: भारत शांति में विश्वास करता है, लेकिन शांति को शक्ति का समर्थन होना चाहिए। अपने मूल में, प्रधानमंत्री मोदी का सिंदूर सिद्धांत तीन अलग सिद्धांतों पर जोर देता है, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पहला, भारत उन देशों के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा, जो आतंक को बढ़ावा देते हैं; जब बातचीत फिर से शुरू होगी, तो यह द्विपक्षीय होगी तथा इसमें केवल आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर चर्चा होगी। दूसरा, भारत आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के साथ आर्थिक संबंधों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है तथा व्यापार और राष्ट्रीय सम्मान के बीच एक सुदृढ़ रेखा खींचता है। अंत में, भारत अब परमाणु धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा- ऑपरेशन सिंदूर ने निर्णायक रूप से उन सभी भ्रमों को तोड़ दिया है कि परमाणु खतरे, आतंकी कृत्यों के ढाल बन सकते हैं।

सिंदूर नाम का चयन गहन सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता को रेखांकित करता है। विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला लाल सिंदूर - पीड़ित होने के रूपक के रूप में नहीं, बल्कि पवित्र कर्तव्य और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। आतंकवादियों ने इस सम्मान को अपवित्र करने की कोशिश की; भारत ने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया। व्यक्तिगत राजनीतिक हो गया, सांस्कृतिक रणनीतिक हो गया। चूंकि आतंकी हमला कश्मीर में हुआ था, जो भारत माता का भौगोलिक और प्रतीकात्मक सिर है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर भारत माता की रक्षा करने और उसे सलाम करने के लिए है। भारत की प्रतिक्रिया एक सैद्धांतिक विरासत का अनुसरण करती है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर 1980 के दशक के इंदिरा सिद्धांत तक तथा 1998 में पोखरण-द्वद्व परीक्षणों के जरिए वाजपेयीजी के साहसिक परमाणु दावे से लेकर —जिसने वैश्विक दबावों और प्रतिबंधों के बावजूद भारत के आत्मरक्षा के संप्रभु अधिकार की पुष्टि की और विश्वसनीय न्यूनतम अवरोध की नीति स्थापित की—से लेकर उरी और बालाकोट में प्रदर्शित मोदी सिद्धांत तक, भारतीय शासन नीति ने लंबे समय से संकट के समय और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मामलों में संप्रभु निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

सिंदूर सिद्धांत इसे आगे बढ़ाता है, आत्मविश्वास से भरे भारत ने इसका समर्थन किया है। देश अपने मूल हितों तथा अपने नागरिकों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए स्वतंत्र व मजबूती से काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भू-राजनीतिक रूप से, इस ऑपरेशन ने क्षेत्रीय उम्मीदों को फिर से स्थापित किया है। आतंकवाद के लिए ढाल के रूप में परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करने के आदी पाकिस्तान का सीधे सामना किया गया है। दंड से मुक्ति का भ्रम टूट गया है।

चीन, हालांकि औपचारिक रूप से तटस्थ है, उसे अपने सहयोगी की कमज़ोरी को समझना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर रूस तक, वैश्विक शक्तियाँ भारत को बाहरी संकेत या समर्थन की प्रतीक्षा किए बिना कार्रवाई करते हुए देख रही हैं। अन्य पड़ोसियों को अब अपनी दुर्भावना और भारत विरोधी कार्रवाइयों के परिणामों का आकलन करना चाहिए।

पिछले 11 वर्षों में, भारत ने कई भौगोलिक क्षेत्रों में और प्रमुख शक्तियों के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी का एक सघन और मजबूत नेटवर्क सफलतापूर्वक निर्मित किया है। इसने बहुपक्षीय और लघुपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय सहयोग व्यवस्थाओं में भाग लिया है और मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, प्रमुख शक्तियों और इन साझेदारियों से जुड़े भारत के कई रणनीतिक और रक्षा संबंध अग्नि परीक्षा से गुजरे।

पहलगाम के बाद, संतोषजनक बात यह थी कि हमारे भागीदारों द्वारा आतंकवादी हमलों की सार्वभौमिक निंदा की गयी। हालाँकि, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान की तीव्र कार्रवाई के बाद, परमाणु-संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ने के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं। प्रतिक्रियाएँ इस बात से भी प्रभावित थीं कि इस सैन्य संघर्ष में उनके हथियार प्रणालियों ने कैसा प्रदर्शन किया या कि क्या प्रदर्शन करने में विफल रहे। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें न केवल अपने रणनीतिक साझेदारों को सावधानी से चुनना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये साझेदारियाँ सिंदूर सिद्धांत को शामिल करती हों।

इसका मतलब यह है कि उन्हें पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसके आतंकी ठिकानों को खत्म करना चाहिए और राज्य-नीति के रूप में आतंकवाद का परित्याग करना चाहिए। यदि हमें पाकिस्तानी आतंकवादी-सैन्य ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उन्हें हमारे साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। दुष्टों के लिए कोई शरणस्थली नहीं, कोई बचाव नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जिस आतंकी ढांचे को निशाना बना रहा है, वह न सिर्फ भारत और लोकतंत्र के लिए, बल्कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि और विकास के इंजन के रूप में देश की भूमिका के लिए भी खतरा है।

पाकिस्तान से आतंकवाद को वैश्विक स्तर पर निर्यात किया जाता है - यूरोप, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका और उससे आगे। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय समुदाय का अधिकांश हिस्सा आंखें मूंद कर बैठा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूह पाकिस्तान में खुलेआम काम करते हैं। पाकिस्तान पहले भी आतंकवादी समूहों की शरणस्थली था और अब भी है। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के दौरान, पाकिस्तान के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से इतना स्वीकार किया। भारत ने आतंक के इस असंख्य सिर वाले राक्षस के खिलाफकार्रवाई करके वैश्विक सेवा की है।

यह अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा के रूप में खड़ा है। दुनिया को कार्रवाई करने के लिए जागरूक होना चाहिए और आतंक के अपराधियों और इसके खिलाफ काम करने वालों के बीच नैतिक समानता स्थापित करना बंद करना चाहिए - चाहे उनके संकीर्ण, अल्पकालिक, दिखावटी विचार कुछ भी हों। सिंदूर सिद्धांत का आर्थिक आयाम भी महत्वपूर्ण है। आतंकवाद के साथ कोई व्यापार नहीं की स्पष्ट घोषणा करके, भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आर्थिक उपायों को क्रियान्वित किया है।

व्यापार और सिंधु जल संधि जैसी संधियों को निलंबित करने जैसे कदम आर्थिक संबंधों को राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के साथ मजबूती से संरेखित करने के भारत के संकल्प को रेखांकित करते हैं। ये उपाय एक स्पष्ट संदेश देते हैं: आतंक के खात्मे के बाद आर्थिक संबंध बनने चाहिए, न कि पहले।

अस्तित्व आधारित संदेश यह है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। नारी-शक्ति से जुड़ा एक शक्तिशाली आख्यान ऑपरेशन के संदेश को पुष्ट करता है और इसे सुर्खियों में लाता है: भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। ऑपरेशन के बाद दो महिला अधिकारियों ने प्रमुखता से सैन्य प्रेस वक्तव्यों का नेतृत्व किया, जो भारत के रक्षा परिदृश्य में महिलाओं के बढ़ते महत्व का प्रतीक है। नारी शक्ति (महिला सशक्तिकरण) के इस क्षण ने महिलाओं के प्रति भारत के सभ्यतागत सम्मान को मजबूत किया, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर समकालीन महिला सैन्य अधिकारियों तक के ऐतिहासिक उदाहरणों की प्रतिध्वनि की, जिससे राष्ट्रीय गौरव को लैंगिक समावेश के साथ जोड़ा गया।

भारत की सैन्य ताकत घरेलू नवाचार की मदद से तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, कुछ विदेशी प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया था, स्वदेशी मिसाइलों, ड्रोन और निगरानी उपकरणों की सफल तैनाती, रक्षा में आत्मनिर्भरता की परिचालन परिपक्वता को उजागर करती है। यह हमारे निर्यात जोर और मांग को बढ़ाता है। हमने भारत में आयातित और सह-निर्मित हथियार प्रणालियों के साथ-साथ पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हथियार प्रणालियों का भी परीक्षण किया और इनसे हमारे द्वारा लिए गए सही निर्णयों की पुष्टि हुई। ऑपरेशन सिंदूर से यह स्पष्ट हो गया कि भारत वैधता नहीं चाहता - वह न्याय चाहता है।

भारतीय संयम को कभी भी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। सिंदूर सिद्धांत केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं है; यह सैद्धांतिक स्पष्टता का एक सक्रिय दावा है। भारत के नागरिकों के, विशेषकर महिलाओं के जीवन, गरिमा, भलाई और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी बिंदु पर राष्ट्रीय सुरक्षा का राष्ट्रीय सम्मान के साथ संगम होता है। यहीं पर प्राचीन मूल्य, आधुनिक ताकत के साथ मिलते हैं। और यहीं पर भारत खड़ा है- निडर, अडिग और एकजुट।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

खास खबर

नगर निगम का अतिक्रमण पर एक्शन, दुकानदारों में मचा हड़कंप

दुर्ग। नगर पालिक निगम/ शहर को बेहतर व सुंदर बनाने की दिशा में बाजार व अतिक्रमण विभाग टीम ने मेयर अलका बाघमार एवं आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश और बाजार अधिकारी शुभम गोइर के दर्शन पर बाजार क्षेत्र पटवा लाइन,कपड़ा लाइन,पांच कंदील,कुनवा चौक में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार भी जारी रहा। इस दौरान अतिक्रमण अधिकारी परमेश्वर कुमार के नेतृत्व में कार्रवाही शुरू किया गया। कार्रवाही के मौके पर उन्होंने दुकानदारों को दुकानों के सामने अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। पटवा लाइन व पांच कंडील बाजार क्षेत्र सडक़ किनारे रखें दुकानो के बाहर विज्ञापन बोर्ड को हटवाया ।साथ ही दुकान के बाहर समान सजाकर रखें कूलर,त्रिपाल,स्टेंड स्टूल सहित चेयर के अलावा सामग्री को जब्त किया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इससे दुकानदारों में हडकंप मच गया,दुकान दार अपना बाहर रखें समान की भीतर रखने लगे। अतिक्रमण अधिकारी परमेश्वर ने दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि दुकानदार दुकानों के सामने अतिक्रमण न करें। अगर कोई दुकानदार अतिक्रमण करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ चालान कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। हथठेले व सडक़ घेरकर पसरा लगाकर दुकानों के बाहर चबूतरा हटवाने की चेतावनी दी कि 24 दिन का समय अगर वह सडक़ पर दिखाई देंगे तो कार्रवाई की जाएगी।

हज पर जा रहे लोगों का सम्मान हम सबका सौभाग्य: रिकेश सेन

भिलाई। शहर से हज्जे बैतुल्लाह जा रहे जायरीनों का इस्तकबाल रविवार 18 मई की रात जुनवानी रोड के एक सभागार में किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल और महापौर परिषद सदस्य इंजीनियर सलमान सहित तमाम मस्जिद कमेटियों के ओहदेदार, मस्जिदों के इमाम-मुअज्जिन और जायरीने हज मौजूद थे। शुरुआत में जामा मस्जिद सेक्टर-6 के इमाम इकबाल अंजुम हैदर ने कुरआन की तिलावत की। उन्होंने इस दौरान कहा कि हज कोई मामूली सफर नहीं बल्कि खास इबादत का सफर है और हमारे बुजुर्गों का तरीका यह रहा है कि इस मुबारक सफर पर जाने वालों का इस्तकबाल करें। उन्होंने हज के दौरान अदा किए जाने वाले अराकान के बारे में बताया और कहा कि वहां आप जितनी और जिस हद तक की कुर्बानी पेश करेंगे उसका उतना ही इनआम आपको मिलेगा। आयोजन में पहुंचे वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने सभी जायरीनों को मुबारकबाद पेश की और सभी का इस्तकबाल किया। उन्होंने सभी जायरीनों से अपील की कि वहां जाने पर हम सबके लिए, अपने देश और प्रदेश के लिए खूब दुआएं कीजिए, जिससे हम सभी आपके इस पुण्य में भागीदार बन सकें।

प्रदेश का पहला रोल बॉल स्केटिंग फ्लोर रिसाली में सांसद बघेल ने कहा अब यहां होंगे राष्ट्रीय मैच

श्रीकंचनपथ न्यूज

रिसाली। प्रदेश का पहला रोल बॉल स्केटिंग फ्लोर का लोकार्पण रिसाली के आत्मानंद गार्डन में रविवार को देर शाम किया गया। इसके निर्माण में 16 लाख 10 हजार राशि खर्च की गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्टेट रोल बॉल एसोशिएसन के अध्यक्ष व दुर्ग सांसद विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, महापौर शशि सिन्हा के आतिथ्य वाले लोकार्पण कार्यक्रम में रोल बॉल स्केटिंग फ्लोर पर 25 से भी अधिक बच्चों ने प्रदेर्शन भी किया।

स्केटिंग फ्लोर के लोकार्पण अवसर पर दुर्ग सांसद और एसोशिएसन के अध्यक्ष विजय बघेल ने कहा कि रिसाली में बने प्रदेश स्तर के पहला स्केटिंग ग्राउण्ड सम्यक प्रयास का परिणाम है। उन्होंने विधायक की सक्रियता और उनकी सोच का उल्लेख करते हुए कहा कि रिसाली भले ही छोटा है, किन्तु यहां उल्लेखनीय कार्य के लिए चिन्हित है। उन्होंने आत्मानंद गार्डन के निर्माण और संचालित गतिविधिया के लिए निगम के सभापति केशव बंछोर को बधाई दी। सांसद ने कहा कि अब रिसाली में भी राष्ट्रीय स्तर व फेडरेशन के खेल आने वाले वर्षो से कराए जाऐंगे।

रिसाली बनेगा रोल मॉडल

दुर्ग ग्रामीण विधायक ने ललित चंद्राकर ने लोकार्पण अवसर पर कहा कि इस ग्राउण्ड से अभ्यास कर बच्चे राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर रिसाली का नाम रोशन करे। यही उनकी इच्छा है। उन्होंने कहा कि विकास एक सतत् प्रक्रिया है। प्राथमिकता के आधार पर कार्य को स्वीकृत कर विकास की कड़ी को जोड़ने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने रिसाली निगम क्षेत्र को प्रदेश में रोल मॉडल बनाकर प्रस्तुत करने की बात कही।

वहीं माहापौर शशि सिन्हा ने अपने उद्बोधन में आत्मानंद गार्डन में बने स्केटिंग फ्लोर के लिए सांसद और विधायक को धन्यवाद ज्ञापित की। महापौर ने सांसद के प्रयास से मिली सौगात को गौरव पूर्ण सौगात होना बताया। लोकार्पण समारोह में स्वागत भाषण सभापति केशव बंछोर व आभार प्रदर्शन आयुक्त मोनिका वर्मा ने की। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू, एमआईसी सनीर साहू, डॉ. सीमा साहू, ममता यादव, पार्षद धर्मेन्द्र भगत, माया यादव, शीला नारखेड़े, सांसद प्रतिनिधि दीपक पप्पू चंद्राकर, मण्डल अध्यक्ष अनुपम साहू, राजू जंघेल आदि उपस्थित थे।

विद्युतीकरण का लोकार्पण

दुर्ग ग्रामीण विधायक ने 18.98 लाख के वार्ड क्र. 23 प्रगतिनगर रिसाली बी.एस.एन.एल. से आशीर्वाद भवन मोड़ तक और वार्ड क्र. 05 एच.एस.सी.एल. कालोनी सियाराम शॉप से ब्लाक ए तक लागत 5.44 लाख से विद्युतीकरण कार्य का लोकार्पण किया।

सिंटर प्लांट-3 में कोक ओवन गैस इंजेक्शन प्रणाली की शुरुआत स्थायी इस्पात उत्पादन की दिशा में बीएसपी का एक महत्वपूर्ण कदम

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के सिंटर प्लांट-3 ने स्थिरता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए मशीन-1 के सिंटर बेड पर कोक ओवन गैस (सीओजी) इंजेक्शन प्रणाली का सफ्लतापूर्वक शुभारंभ किया है। यह प्रणाली संयंत्र के इस हिस्से में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से विकसित की गई है।

निदेशक तथा अतिरिक्त प्रभार निदेशक प्रभारी मनीष राज गुप्ता द्वारा इस प्रणाली का औपचारिक उद्घाटन 17 मई 2025 को किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (संकार्य) राकेश कुमार सहित संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा शीर्ष प्रबंधन के सदस्य उपस्थित रहे।

यह परियोजना, जो डी-कार्बनाइजेशन की दिशा में एक अग्रणी प्रयास है, महाप्रबंधक प्रभारी (सिंटर प्लांट्स) अनुप कुमार दत्ता के मार्गदर्शन में प्रारंभ की गई तथा महाप्रबंधक (संचालन) आर. डी. शर्मा के नेतृत्व में क्रियान्वित की गई। कोक ओवन गैस, जो एक उच्च कैलोरी मान वाला उप-उत्पाद है, को सहायक ईंधन के रूप में उपयोग कर सिंटर उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य रहा है।

इस संपूर्ण परियोजना का निष्पादन संयंत्र की यांत्रिक, विद्युत एवं इंस्ट्रूमेंटेशन टीमों द्वारा संयंत्र के भीतर ही किया गया। इस कार्य में मुख्य महाप्रबंधक (सिंटर प्लांट-3) श्री सजीव वर्गीज की समन्वयनात्मक भूमिका उल्लेखनीय रही। तकनीकी दृष्टि से, सिंटर बेड में सीओजी के इंजेक्शन से प्रति टन सिंटर उत्पादन में लगभग 2 किलोग्राम कोक की बचत संभव हो पाती है। इससे न केवल सिंटर की गुणवत्ता में सुधार होता है और रिटर्न फाइन्स की मात्रा घटती है, बल्कि सीओ२ उत्सर्जन में भी वार्षिक अनुमानित 12,700 टन की कमी दर्ज की जा सकती है। साथ ही, ईंधन दक्षता में वृद्धि और लागत में उल्लेखनीय बचत होती है, जिससे संयंत्र की हरित इस्पात निर्माण की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।

सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए परियोजना के अंतर्गत अत्याधुनिक सुरक्षा एवं निगरानी प्रणालियों की भी व्यवस्था की गई है। इनमें सीओ गैस डिटेक्टरों की स्थापना, संचालन क्षेत्र में रणनीतिक स्थानों पर निगरानी कैमरों की तैनाती तथा सीओजी इंजेक्शन नेटवर्क में फ्लो और प्रेशर के लिए रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं। कोक ओवन गैस इंजेक्शन प्रणाली का सफल क्रियान्वयन भिलाई इस्पात संयंत्र की नवाचार-प्रेरित प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है। यह पहल पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रति संयंत्र के दूरदर्शी दृष्टिकोण को सशक्त करती है और हरित औद्योगिक भविष्य के निर्माण हेतु उसकी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूती प्रदान करती है।

जनमन पत्रिका का वितरण, योजनाओं की जानकारी पहुंची जनता तक

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। सुशासन तिहार के अंतर्गत अंजोरा (ख) में आयोजित समाधान शिविर में शासन की मासिक पत्रिका 'जनमन' का वितरण किया गया। इस पत्रिका में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और नवाचारों की जानकारी दी गई। पत्रिका के माध्यम से आम नागरिक यह जान पाएंगे कि उनके हित में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों एवं शिविर में 15 ग्रामों से आए ग्रामीणजनों को जनमन की प्रतियां एवं पाम्पेट वितरित की गई। ग्रामीणों ने भी जनहित की योजनाओं के बारे में पढ़ने में रुचि दिखाई। संयुक्त कलेक्टर, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, तहसीलदार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कसारीडीह, गुरुघासीदास वार्ड 44 में नाली में डिस्पोजल देखकर सुपर वाइजर पर भड़की मेयर

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग अंतर्गत वार्ड कसारीडीह गुरुघासीदास वार्ड 44 में महा अभियान नाली साफ-सफाई को लेकर मेयर अलका बाघमार द्वारा प्रभारी नीलेश अग्रवाल,नरेंद्र बंजारे वार्ड पार्षद मनीष कोठारी, उपअभियंता विनोद मांझी,प्रेरणा दुबे,सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पंकज,सुरेश भारती सहित अमला के संग निरीक्षण करने पहुंचे।

उन्होने कसारीडीह से लगी हुई गुरुघासी दास वार्ड बस्तीयो के गलियों व सडक़ों में पैदल भ्रमण कर साफ सफाई व्यवस्था को देखे। वार्ड क्रमांक 44 क्षेत्र के कसारिडीह चौक में अगल-बगल कुछ दुकानदारों द्वारा नालियों पर अवैध अतिक्रमण कर रखा गया है, जिसके कारण नाली सफाई नहीं हो पा रहा है। जिसे हटाने के निर्देश अधिकारियो को दिये ।कसारिडीह, गुरुघासीदास वार्ड में नाली में डिस्पोजल देखकर सुपर वाइजर पर भड़की कहा कही भी नालियों में दोबारा ऐसी नॉबत न आए।

मेयर बाघमार ने सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एवं वार्ड प्रभारी इंजीनियरों से कहा कि अवैध रूप से निगम की जमीन पर बिल्डिंग मटेरियल रख कर मकान निर्माण करने वाले। सहित बिल्डिंग मटेरियल व्यापार करने वाले व्यापारियो का गुमस्ता एवं ट्रेड लाईसेंस निरस्त कर चालानी कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार इडब्लू एस कालोनी क्षेत्र में नालियों के उपर अवैध कब्जा किया गया है, जिसे हटाकर स्थल की साफ-सफाई कराने को कहा है ।उन्होंने अधिकारी को वार्ड में जाकर उसे नोटिस देकर अवैध कब्जा करने वालो पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। मेयर ने वार्ड के नागरिकों से सफाई के संबंध में चर्चा की। उन्होंने नाली सफाई, रोड़ सफाई के बारे में जानकारी ली। लोगों ने कहा कि नाली व रोड़ की सफाई होती है, घर-घर कचरा लेने भी स्वच्छता दीदी आती है।

उन्होंने खाली प्लाट में कचरा एवं झिल्ली पन्नी बिखरा देख प्लाट के मालिक को नोटिस देने कहा। साथ ही कचरा एवं झिल्ली पन्नी फेंकने वाले की पहचान कर जुर्माना लगाने निदेशित किया। गुरुघासी दास क्षेत्र में पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो, यूजर को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

संयंत्र के ऑक्सीजन प्लांट-2 में मॉक ड्रिल का सफल प्रदर्शन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के ऑक्सीजन प्लांट-2 (ओपी-2) स्थित तरल ऑक्सीजन टैंक-1 में एक संभावित खतरनाक स्थिति-तरल ऑक्सीजन रिसाव-की परिकल्पना पर आधारित एक व्यापक संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन 19 मई 2025 को किया गया। यह मॉक ड्रिल राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल , केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल , राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल तथा बीएसपी के विभिन्न विभागों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य औद्योगिक दुर्घटनाओं, विशेष रूप से क्रायोजेनिक पदार्थों से जुड़ी आपात स्थितियों में तैयारियों और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का परीक्षण करना था।

19 मई 2025 के प्रात: काल लगभग 10:30 बजे, प्रिपरेटरी मॉक ड्रिल गतिविधि के अंतर्गत, यांत्रिक समूह के छह कर्मी तरल ऑक्सीजन टैंक-1 के सिलेंडर फिलिंग पंप में एसएस यूनियन से रिसाव की शिकायत पर ब्रेकडाउन अनुरक्षण कार्य में संलग्न थे। अनुरक्षण के दौरान, लोकल वाल्व बंद करने के पश्चात जब एसएस यूनियन को ढीला किया जा रहा था, तो फ्लैंज पैकिंग को क्षति पहुँची, जिससे अचानक और अनियंत्रित रूप से तरल ऑक्सीजन (एलओएक्स) का रिसाव होने लगा। रिसाव की चपेट में आए चार कर्मियों को संभावित कोल्ड बर्न का खतरा उत्पन्न हुआ। -183 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली तरल ऑक्सीजन के रिसाव से गंभीर कोल्ड बर्न तथा उच्च ऑक्सीजन वातावरण में लंबे समय तक रहने पर गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं और अग्नि जोखिम की आशंका रहती है। तरल ऑक्सीजन का रिसाव एक गंभीर दुर्घटना को जन्म दे सकता था।

जैसे ही रिसाव हुआ, यांत्रिक कर्मचारियों ने तत्काल चेतावनी दी और पास में कार्यरत विद्युत कर्मियों ने घटना की सूचना ओपी-2 के शिफ्ट मैनेजर को दी। स्थिति का आकलन कर आपात प्रोटोकॉल सक्रिय किए गए।

सहायक प्रबंधक हेमंत कुमार अमरिया, जो घटनास्थल की निगरानी कर रहे थे, ने इंसिडेंट कंट्रोलर की भूमिका निभाते हुए आपातकालीन सायरन बजाया एवं महाप्रबंधक मोहम्मद नदीम खान को सूचना दी, जिन्होंने वर्क इन्सिडेंट कंट्रोलर की भूमिका में मुख्य महाप्रबंधक जे पी सिंह, चीफ इन्सिडेंट कंट्रोलर, को सूचित किया। इसके बाद तत्काल निकासी आदेश जारी किए गए और ओपी-2 कंट्रोल रूम द्वारा सभी आपात एजेंसियों को संदेश भेजा गया। घटना की सूचना 11:22 बजे दर्ज की गई और 11:28 बजे आपातकालीन सायरन बजाया गया और सभी सम्बंधित एजेंसियों को सूचना दी गयी। सीआईएसएफ की टीम पहुँची और क्षेत्र की घेराबंदी कर अनधिकृत प्रवेश को रोका एवं वाहन संचालन नियंत्रित किया।

अन्य विभागीय एवं बाह्य एजेंसियाँ जैसे कि एसईडी, सिविल डिफेंस, पर्यावरण प्रबंधन, गैस सुरक्षा, एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ की टीमें भी 11:35 बजे के बीच पहुँच गईं और स्थिति पर तत्काल नियंत्रण करने और फाल्ट को दुरुस्त करने का प्रयास किया गया। स्थिति पर नियंत्रण पाते ही ऑल क्लियर सायरन 11:52 बजे बजाया गया। महाप्रबंधक (एसईडी) एवं नोडल अधिकारी एस आर शेंडे ने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा महाप्रबंधक (एसईडी) पी एम राजेन्द्र कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। संयंत्र की सुरक्षा संरचना की संपूर्ण कार्यकुशलता और विभिन्न एजेंसियों के बीच सुचारू समन्वय को यह मॉक ड्रिल एक बार पुन: सफ्लतापूर्वक दर्शाने में सक्षम रही।

Since 1972
CROWN® - TV
Choice Of Millions
LED Available 16 -20 -22 - 24 - 32-40-50-55-65

Maa Durga Electronics 9827183839
Rohit Electronics 94242-02866
Premier sales: 8959493000
A Leela Electronics: 9425507772
Reena Electronics: 9329132299
Shree Electronics: 7000827361
Authorised Distributers For Chhattisgarh
Trade Enquiry: 98262-52372

खास खबर...

लेखा प्रशिक्षण सत्र जुलाई-अक्टूबर के लिए लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के आवेदन 31 मई तक आमंत्रित

रायपुर। संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार प्राचार्य शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला रायपुर द्वारा आगामी लेखा प्रशिक्षण सत्र जुलाई–अक्टूबर 2025 के लिए आवेदन पत्र 31 मई 2025 तक आमंत्रित किए गए हैं। संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरा कर चुके लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित आवेदन पत्र शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला, नगर घड़ी चौक रायपुर को 31 मई 2025 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त हो जाना चाहिए।

इस संबंध में शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला के प्राचार्य द्वारा स्पष्ट किया गया है कि लिपिकीय वर्गीय कर्मचारी से आशय ऐसे कर्मचारी से है, जिनकी पदस्थापना लिपिकीय संवर्ग के पद पर हुई है न कि किसी तकनीकी संवर्गीय पद पर है। इस तिथि के पूर्व एवं पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ नोटराइज्ड शपथ–पत्र संलग्न होना अनिवार्य है। विज्ञप्ति के साथ संलग्न (छायाप्रति स्वीकार्य) मानक आवेदन पत्र पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन जिस सत्र के प्रशिक्षण हेतु किया गया है, उस सत्र के लिए ही मान्य होगा। पूर्व प्रचलित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ड्यूटी में मौत पर मिलेंगे 15 लाख, ट्रांसमिशन कंपनी ने 1431 अधिकारियों-कर्मचारियों का करवाया बीमा

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने अपने अधिकारियों –कर्मचारियों का सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी कराई है। मानव संसाधन विभाग ने परिपत्र जारी कर सूचित किया कि बीमा अवधि 06 मई 2024 (00.00 बजे) से 1 वर्ष के लिए प्रभावशील है। वर्ष 2025–26 के लिए ट्रांसमिशन कंपनी ने 1431 अधिकारियों– कर्मचारियों के लिए बीमा करवाया है। योजना के तहत कार्य अवधि में मृत्यु होने पर जोखिम राशि रुपए 15 लाख एवं कार्य अवधि के अलावा अन्य अवधि में दुर्घटनावश मृत्यु होने पर राशि रुपए 5 लाख प्रति कार्मिक का प्रावधान किया गया है।

संबंधित कार्यालय द्वारा दुर्घटनावश मृत्यु की जानकारी अनिवार्य रूप से बीमा कंपनी को 24 घंटे के अंदर देना सुनिश्चित करना होगा। साथ ही 30 दिन के अंदर निर्धारित दावा प्रपत्र एवं समस्त वांछित दस्तावेजों की 3 प्रतियां व्यक्तिगत रूप से उप महाप्रबंधक (औद्योगिक संबंध) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी कार्यालय से परीक्षण कराके बीमा कंपनी को भेजना अनिवार्य होगा। दस्तावेजों को वरिष्ठ व्यावसायिक प्रबंधक, मेसर्स दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, प्रमुख व्यावसायिक कार्यालय, एमआईजी – 15,शंकर नगर, सेक्टर 3,रायपुर,छत्तीसगढ़, पिन नं. –492004, दूरभाष क्रमांक 9425540156 को प्रेषित करना होगा। बीमा कंपनी द्वारा 30 दिन के अंदर दावा राशि का भुगतान किया जावेगा। यह योजना गैर अंशदायी प्रकृति पर आधारित है, यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा वार्षिक प्रीमियम राशि,बीमा कंपनी को प्रदान की गयी है।

प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में संविधान संशोधन व सदस्यता शुल्क पर लगी मुहर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। सिंधु पैलेस शंकर नगर में छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत की प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई जिसमें रायपुर के साथ पूरे प्रदेश से समाज के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने प्रमुख विषय जैसे की संविधान संशोधन सदस्यता शुल्क आजीवन मेंबरशिप आदि तथा सदस्यता शुल्क पर अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान झूलेलाल की प्रतिमा पर दीप प्रज्वल करके किया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष महेश दरयानी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत की वर्तमान कार्यकारिणी निरंतर अपने वादे पूरे कर रही है तथा कार्यकाल पूर्ण होते तक सभी वादे पूर्ण किए जाएंगे यह में समाज को विश्वास दिलाता हूं।

वहीं पंचायत के संरक्षक अमर पारवानी ने कहा कि समाज को अपना राजनीतिक वजूद के साथ अब अपने बच्चों को प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कि समाज की मजबूत उपस्थिति शासन प्रशासन व राजनीतिक दलों में दर्ज की जा सके साथ ही पंचायत की वर्तमान कार्यकारिणी को बड़े और ठोस निर्णय लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि सिंधी समाज के साथ अन्य समाज भी हमसे प्रेरणा लें। एक प्रेस विज्ञप्ति में पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष महेश दरयानी व प्रदेश प्रवक्ता सुभाष बजाज ने बताया

कि प्रमुख विषयों पर समाज की जो राय आई वह इस तरह रही की छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत को अब छत्तीसगढ़ पूज्य सिंधी पंचायत लिखा जाएगा।

पिछली कार्यकारिणी की बैठक में बनाई गई संविधान संशोधन समिति के सदस्य कैलाश बालानी ने पूर्व के संविधान के बिंदुओं को सामने रखकर जानकारी दी कि किन–किन बिंदुओं पर संशोधन किए जाने का प्रस्ताव समिति द्वारा बनाया गया है जिस पर आज उपस्थित कार्यकारिणी ने अपना अनुमोदन किया। आयोजन में मुख्य रूप से अमर पारवानी मुरलीधर उदासी, महेश दरयानी, महेश रोहरा बलराम आहूजा, अमित चिमनानी, रमेश मिरघानी, मन्नूमल पृथ्वानी, कैलाश बालानी, सुभाष बजाज, तनेश आहूजा, विकास रूपरेला अनिल लाहोरी, अनूप मसंद, हेमा अमेसर, कनक खेमानी, चंचल बजाज, अमर चंदनानी गौरव मंघानी, अनेश बजाज, सतीश छुगानी, प्रहलाद शादीजा, जीवत बजाज, कैलाश खेमानी, भारत चंदवानी, जीतू नेभवानी, गिरीश लहेजा, विक्रम केवलानी प्रकाश सोनवानी राजू चंदनानी, मनीष पंजवानी, रतन वलयानी धनराज मध्यानी, राजिम पंचायत, सुरेश सिदारा, धनराज आहूजा, बिलासपुर पंचायत चंदू जसवानी, धमतरी पंचायत राकेश मंधानी तखतपुर पंचायत राजा माखीजा, संजय तेजवानी गुरमुखदास वाधवा राजनांदगांव इंदर थारानी, भीष्म गुरियानी, भाटापारा पंचायत सुरेश फुटानी, चकरभाटा पंचायत मनीष आहूजा सनी मलानी, निक्की दसवानी, प्रेम प्रकाश मध्यानी, संजय पोपटानी, रागीनी गोगीया, दिक्षा रॉमानी, दिपा सुखरामानी, हर्षा सुंगध, अजीत मोटवानी, सहित पूरे प्रदेश से सामाजिक प्रतिनिधि शामिल हुए। आयोजन का संचालन प्रहलाद शादीजा व तनेश आहूजा तथा आभार प्रदर्शन बलराम आहूजा ने किया।

छत्तीसगढ़ में जल संकट गहराया

पांच प्रमुख बांध पूरी तरह सूखे

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ इस समय गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। राज्य के पांच प्रमुख बांध मुरूमसिल्ली, मोगरा बैराज, पेंड्रावन, मयाना और घुमरिया पूरी तरह से सूख चुके हैं। साथ ही आठ अन्य बांधों में जल स्तर 10 प्रतिशत से भी नीचे पहुंच गया है। लगातार तीसरे वर्ष जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है, जो चिंता का विषय है।

छत्तीसगढ़ में गर्मी के मौसम के साथ ही जल संकट की स्थिति भयावह होती जा रही है। राजधानी रायपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं। विशेष रूप से राज्य के पांच प्रमुख बांध मुरूमसिल्ली, मोगरा बैराज, पेंड्रावन, मयाना और घुमरिया का जल स्तर शून्य प्रतिशत पर पहुंच चुका है, जिससे कृषि, पेयजल और पर्यावरणीय संतुलन पर गहरा असर पड़ा है।

राज्य जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, इन बांधों का जलस्तर पिछले तीन वर्षों में लगातार गिरता जा रहा है। जहां मुरूमसिल्ली डैम 2023 में 31.5 प्रतिशत जल से भरा था, वहीं 2024 में यह पूरी तरह खाली हो गया और 2025 में सिर्फ 0.01 प्रतिशत जल शेष रह गया। इसी प्रकार, मोगरा बैराज में 2023 में 14 प्रतिशत जल था, जो 2024 में घटकर 20 प्रतिशत और अब 2025 में पूरी तरह सूख गया है।

इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार सूखे और मानसून की अनियमितता के कारण यह स्थिति बनी है। इसके अतिरिक्त, जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल संचयन और जल उपयोग में अनुशासन की कमी भी इस संकट के पीछे प्रमुख कारण हैं।

इस जल संकट के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेती बुरी तरह प्रभावित हो रही है। साथ ही शहरी इलाकों में भी पेयजल की किल्लत महसूस की जा रही है। जल संकट के इस दौर में राज्य सरकार और जल संसाधन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती है–स्थायी समाधान खोजना और जल प्रबंधन के लिए प्रभावी रणनीति अपनाना। जल विशेषज्ञों का कहना है कि वर्षा जल संग्रहण, छोटे जलाशयों का निर्माण, गांव–गांव में तालाबों की पुन:खुदाई और जल साक्षरता अभियान चलाना समय की मांग है। अगर अभी से प्रभावी प्रयास नहीं किए गए, तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को पीने के पानी के लिए भी संकट का सामना करना पड़ सकता है।

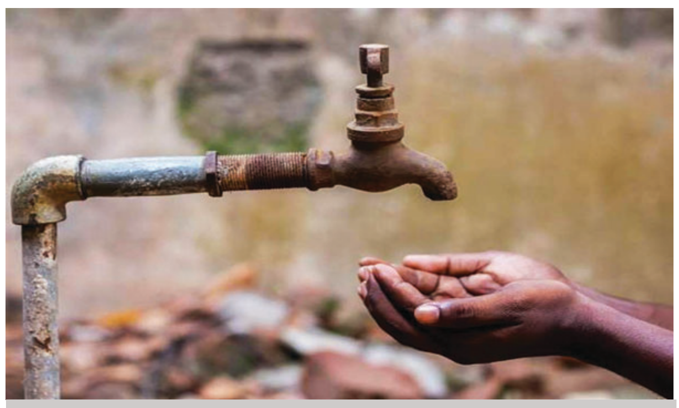

बांधों के जल स्तर का तुलनात्मक आंकड़ा (प्रतिशत में)

बांध	2025	2024	2023
मुरूमसिल्ली	0.01%	0.00%	31.5%
मोगरा	0.00%	20%	14%
पेंड्रावन	0.00%	5.3%	16.8%
मयाना	0.00%	2.8%	20.3%
घुमरिया	0.00%	1.1%	14.3%

एमआईसी मेंबर ने मैकेनाइज्ड स्वीपिंग कार्य का किया निरीक्षण

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर नगर निगम की एमआईसी मेंबर गायत्री सुनील चंद्राकर ने कल रात टाटीबंध चौक से शास्त्री चौक तक शहर की स्वच्छता व्यवस्था हेतु मैकेनाइज्ड स्वीपिंग कार्य का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने आधुनिक मशीनों के माध्यम से की जा रही सड़क सफाई प्रक्रिया को देखा और सफाई कर्मचारियों से भी चर्चा की। निरीक्षण के दौरान चंद्राकर ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मैकेनाइज्ड स्वीपिंग के दौरान गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मशीनों की नियमित देखरेख, समय पर संचालन और कचरा निस्तारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आवश्यक है।

उन्होंने सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सुझाव भी दिए, जैसे कि–प्रमुख सड़कों के अलावा आंतरिक गलियों में भी मशीनों का उपयोग बढ़ाया जाए, और नागरिकों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। चंद्राकर ने यह भी कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत रायपुर शहर को स्वच्छता के मामले में शीर्ष स्तर पर लाना निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से निरीक्षण करें और जनता से फीडबैक लेकर सुधार की दिशा में कदम उठाएं।

सरकार की नई पहल: कॉलेजों में पढ़ाई के साथ छात्र सीखेंगे कौशल विकास

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नौ कॉलेज में नए शिक्षा सत्र से अब पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को कौशल विकास और उद्योग कुशल के भी गुर सिखाए जाएगें। कालेज से डिग्री लेकर निकलने वाले विद्यार्थी रोजगार के लिए यहां–वहां न भटके इसके लिए राज्य शासन ने पहल की है। राज्य के उद्योग अकादमी सहयोग प्रकोष्ठ ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। पहले चरण में राज्य के नौ कॉलेजों का चयन किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के उद्योग अकादमी सहयोग प्रकोष्ठ द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों के कौशल विकास तथा उन्हें उद्योग कुशल बनाने के लिए पिंक एप्रेन्टिसशिप तथा इंटर्नशिप प्रोग्राम लांच किया गया है। नए शिक्षा सत्र में राज्य के नौ कालेजो के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रकोष्ठ ने इन कालेजो के प्राचार्यों को पत्र लिखकर उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों की मैपिंग का काम पूरा करने के निर्देश दिए है। यह भी कहा गया है कि कालेज से 25 किलोमीटर की अवधि में ही उद्योगों, एनजीओ तथा प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया जाए।

पढ़ाई के साथ – साथ विद्यार्थियों को पीआईपी के तहत स्वास्थ्य कल्याण सेवा एवं मेडिकल सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आईटी एवं डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, सरकारी एवं सार्वजनिक प्रशासन संस्थान, मीडिया एवं कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट एवं पर्यटन उद्योग, फैशन एवं कपड़ा उद्योग, सोशल वर्क एवं एनजीओ, हस्तकला एवं शिल्प उद्योग ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, सौंदर्य कला एवं प्रसाधन उपचार आधारित उद्योग के साथ साथ महाविद्यालय के निकट संचालित उद्योग में ट्रेनिंग दी जाएगी।

कौशल विकास और उद्योग कुशल के लिए शासकीय नागार्जुन विज्ञान कॉलेज रायपुर, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला कॉलेज रायपुर, शासकीय जे योगानन्दम छत्तीसगढ़ कालेज रायपुर, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, शासकीय दाउ कल्याण कला एवं वाणिज्य कालेज बलौदाबाजार, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर कालेज धमतरी तथा आचार्य पंथ श्री ग्रंथ मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर कालेज कवर्धा का चयन किया गया है।

महोबा बाजार में पॉलीथिन जब्त, नगर निगम रायपुर ने की चालानी कार्यवाही

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के आदेशानुसार और जोन 8 जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 8 क्षेत्र के अंतर्गत महिला स्वसहायता समूह की स्वच्छता दीदियों सहित नगर निगम जोन 8 के जोन स्वास्थ्य अधिकारी गोपीचंद देवांगन एवं सफाई मित्रों द्वारा मोहबा बाजार में मेरा बाजार स्वच्छ बाजार अभियान चलाकर जनजागरण किया गया। वहीं प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर विशेष मुहिम चलायी गयी, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यवाही की गयी, जिसमें दुकानदारों को पॉलीथिन न रखने की समझाईश दी गयी एवं चालानी कार्यवाही की गई । साथ ही कपड़े का बैग रखने और ग्राहकों को प्रदान करने कहा गया । इस दौरान पॉलीथिन को जप्त किया गया।

मां कौशल्या धाम के निर्माण के लिए यह समझकर योगदान करें कि हमारी मां का मंदिर बन रहा है - कौशल्या साय

श्रीकंचनपथ न्यूज

बालोद। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ श्री पाटेश्वर आश्रम में मुख्यमंत्री की पत्नी कौशल्या साय ने पूजा अर्चना किया। साध्वी प्रज्ञा भारती ने संत राम बालक दास से आशीर्वाद लिया। साध्वी प्रज्ञा ने पूज्य राजयोगी बाबा के समाधि का पूजन किया और मां कौशल्या धाम के नवनिर्मित मन्दिर में जाकर भगवान शिव का भी पूजन किया।

इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कौशल्या साय ने कहा कि मां कौशल्या धाम के निर्माण हमारे माँ के मंदिर का निर्माण है ऐसा समझकर संपूर्ण बालोद जिला एवं छत्तीसगढ़ और देश के लोगों को अपना योगदान करना चाहिए।

संत राम बालक दास के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते उन्होंने कहा कि संत ने अपने ही नहीं बल्कि अपने मातृभूमि के नाम को अमर किया है अब हमारी बारी है क्योंकि 2026 में मां कौशल्या की विश्व में प्रथम प्रतिमा का यहां स्थापना होना है। अत: हम सबको भी अपने नाम को अमर करना चाहिए और योगदान देना चाहिए। श्री पाटेश्वर धाम परिक्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की उन्होंने अवलोकन किया और कहा कि जितने भी निर्माण कार्य अधूरे हैं उन सब को जल्दी ही पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जून में मुख्यमंत्री के साथ पुन: मां कौशल्या धाम आएंगी। इसके पश्चात गौशाला में जाकर पूजन भी किया और संत राम बालक दास ने सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर संत राम बालक दास ने कहा कि कौशल्या साय का पाटेश्वर धाम आना इस बात का संकेत है कि वर्तमान छत्तीसगढ़ शासन संतों के प्रति संवेदनशील है और मां कौशल्या धाम के निर्माण के लिए हमारे साथ है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक 29 को

रायपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक रायपुर में होने जा रही है। वीन दिवसीय बैठक में शिक्षा और सामाजिक विषयों पर आधारित प्रस्ताव पारित किए जाएंगी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्त, वक्फ बोर्ड बिल और अन्य शिक्षा संबधी समसामयिक मुद्दे भी होंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 29 से 31 मई तक होने वाली इस बैठक में एबीवीपी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसमें मिजोरम, नेपाल, सिक्किम, केरल और कश्मीर समेत देशभर के 700 प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह मुकुंद सियार कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे।

सोनाक्षी सिन्हा की साइकोलॉजिकल थ्रिलर निकिता रॉय का पोस्टर रिलीज

हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म निकता रॉय का पोस्टर रिलीज हुआ है। अभिनेत्री के इस फिल्म के पोस्टर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। सोनाक्षी के तनाव और सीरियस लुक ने सभी को हैरान कर दिया है। फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म की रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी गई है।

सोनाक्षी सिन्हा अपने दमदार लुक के साथ इस बार सिनेमाई पर्दे पर नजर आने वाली हैं। अभिनेत्री की आगामी फिल्म निकिता रॉय के पोस्टर ने उनके लुक के बारे में कई सवाल पैदा कर दिए हैं। इस पोस्टर में सोनाक्षी सिन्हा के अलावा अर्जुन रामपाल, परेश रावल और सुहैल नय्यर भी नजर आ रहे हैं। फिल्म के पोस्टर में सभी किरदार सस्पेंस लुक में दिख रहे हैं। यह फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है।

निकिता रॉय फिल्म का निर्देशन कुश एस सिन्हा कर रहे हैं, जो इस फिल्म से डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू कर रहे हैं। यह फिल्म रहस्य, मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की कहानी के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। सोनाक्षी सिन्हा की ये फिल्म 30 मई को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म को निक्की विक्की भगनानी फिल्म्स और निकिता पाई फिल्म्स लिमिटेड के बैनर तले बनाया जा रहा हैं। वहीं, इस फिल्म का प्रोडक्शन निक्की खेमचंद भगनानी, किंजल आहूजा घोन और विक्की भगनानी ने किया है।

सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत फिल्म निकिता रॉय को लेकर फिल्म निर्माता निक्की और विक्की भगनानी ने कहा कि यह फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है। यह फिल्म दर्शकों को वहां ले जाएगी, जहां मुख्यधारा की फिल्में नहीं ले जा पाती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस फिल्म के कलाकार अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन करने को तैयार है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म रिलीज के समय पर सिनेमाघरों में क्या कमाल करती है।

हर उस दिल की धड़कन के साथ हूं, जो हमारे देश के लिए धड़कती है: करिश्मा तन्ना

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। भारतीय सेना पाकिस्तान की हरकतों का करारा जवाब दे रही है। पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी खुलकर सरहद पर देश की रक्षा करने वालों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इस कड़ी मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने भारतीय सैनिकों को सलाम करते हुए कहा कि वह हम आपकी वजह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

करिश्मा तन्ना ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा , जय हिंद, जय भारत.. इस समय, जो हम अपना जीवन सुख से जी रहे हैं। इसके पीछे हमारी सीमाओं पर खड़े बहादुर सैनिक हैं, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हमें सुरक्षित महसूस करा रहे हैं। हर सैनिक, हर अधिकारी, हर परिवार.. जो चुपचाप डटे हुए हैं, उनके प्रियजन हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद कहना बहुत छोटा लगता है। मैं भारत के साथ खड़ी हूं। हर जवान के साथ। हर उस दिल की धड़कन के साथ, जो हमारे देश के लिए धड़कती है। आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूं। आपके साहस को सलाम करती हूं। भारत आपके कारण है। जयहिंद, जय भारतीय सेना।

करिश्मा के अलावा, बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही ने भी भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के पोस्ट पर लिखा, प्रिय भारतीय सेना, इन मुश्किल परिस्थितियों में मैं आप सभी को आपके अटूट साहस, बलिदान और समर्पण के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं। भारत की सुरक्षा व संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए आपकी लगातार की जा रही कोशिशें नजरअंदाज नहीं की जा सकती। देश मुश्किल हालातों से गुजर रहा है, ऐसे समय में भारतीय सैनिकों की हिम्मत और समर्पण आम लोगों को प्रेरणा और सकारात्मक उम्मीद दे रही है। गर्व और सम्मान के साथ भारत की रक्षा करने और मजबूती से खड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम भारत और सशस्त्र बलों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं! हमारे असली हीरो! जय हिंद!

वहीं एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय ने इंस्टाग्राम पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पोस्ट शेयर किया था। पोस्ट पर लिखा था, जब किसी महिला के सामने उसके पति को मार दिया जाता है, तो पूरा देश केवल शोक नहीं करता, बल्कि जाग उठता है। आज ये दोनों महिला अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी केवल फौजी अफसर की तरह नहीं बोलींज बल्कि वे प्रतीक बन गईं उन हर महिलाओं की, जिन्होंने अपने दु:ख को शक्ति में बदला, उन हर माताओं की, जिन्होंने अपने बच्चों को राष्ट्र सेवा के लिए भेजा। ऑपरेशन सिंदूर बदला नहीं है, यह एक चेतावनी है- जब भारत के दिल पर चोट की जाती है, तो दुर्गा उठ खड़ी होती है। इस बार, वह दुर्गा आशीर्वाद देने नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए आ रही है।

भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कार्रवाई को लेकर कई सितारे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि अब भारत और पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का ऐलान कर दिया गया है।

देश सबसे पहले: तुर्किये बॉयकॉट पर बोलीं मंजरी फडनीस

भारत-पाकिस्तान तनाव पर पड़ोसी देश का समर्थन करने वाले तुर्किये का आम लोगों के साथ ही फिल्म जगत के सितारे भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। भारत में तुर्किये बॉयकॉट की मांग उठने लगी है। अभिनेत्री रूपाली गांगुली, कुशाल टंडन, विशाल मिश्रा के बाद अब अभिनेत्री-गायिका मंजरी फडनीस की प्रतिक्रिया सामने आई है।

मंजरी ने तुर्किये बॉयकॉट पर कहा कि वह देशभक्त हैं और सबसे पहले देश आता है। जब उनसे पूछा गया कि तुर्किये और अजरबैजान जैसे देशों ने आतंकवाद पर पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन किया है तो क्या पर्यटन और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए?

इस पर फडनीस ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी ऐसे देश या व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकतीं जो उनकी मातृभूमि का अनादर करता है या उसका विरोध करता है। उनके लिए, राष्ट्रीय गौरव और निष्ठा सबसे पहले है। वह हर चीज से ऊपर अपने देश के साथ मजबूती से खड़ी रहना पसंद करती हैं। मंजरी फडनीस ने बताया, कोई भी देश या व्यक्ति जो मेरे देश का अनादर करता है या उसके खिलाफ खड़ा होता है, मैं उनका समर्थन नहीं कर सकती। मेरी निष्ठा हमेशा मेरे देश के प्रति है।

अभिनेत्री–गायिका ने बताया, मेरे घर का माहौल देशभक्ति वाला रहा है। मैं एक आर्मी परिवार से ताल्लुक रखती हूं, मेरे पिता ने सेना में ड्यूटी की है। मैं देशभक्त हूं। मैंने अपना पूरा बचपन सेना के अधिकारियों के बीच बिताया। मैंने खुद देखा है कि भारतीय सेना कैसे काम करती है और वे कितने समर्पित और अनुशासित हैं। उस अनुभव ने मुझे देश के साथ गहरा और मजबूत संबंध बनाने में मदद की।

बातचीत के दौरान मंजरी ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया, जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पर आप पोस्ट शेयर नहीं कर रहे हैं तो देश के प्रति आपकी भावनाएं नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे देश ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, उस पर मुझे गर्व है। मुझे लगता है कि हम सभी देश के लिए एकजुटता में एक साथ आए हैं, देश की एकता देखन को मिली।

व्हाइट टॉप और डेनिम में मोनालिसा का स्टाइलिश अंदाज, एक्ट्रेस की फिटनेस देख मोहित हुए फैंस

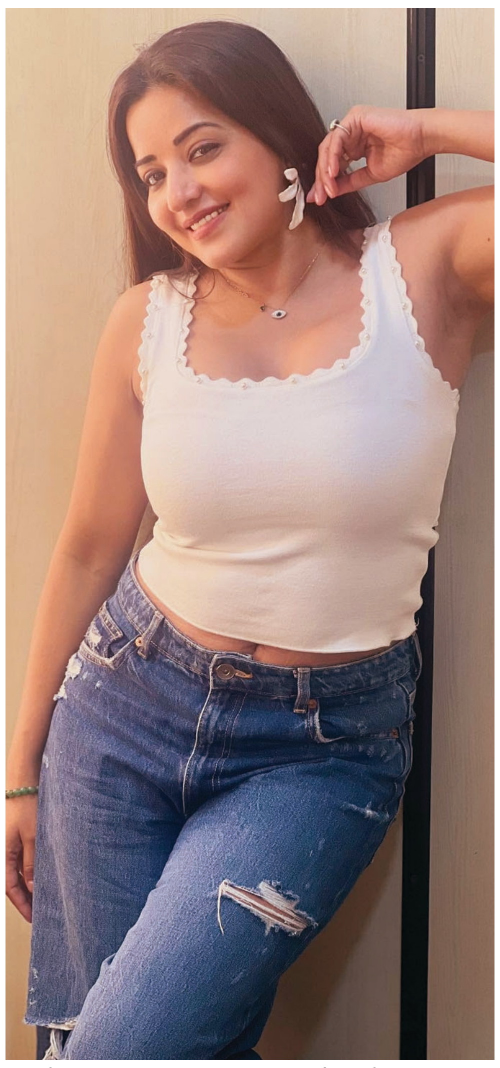

भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस मोनालिसा एक बार फिर अपने ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट लुक से सोशल मीडिया पर छा गई हैं। हाल ही में मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद स्टाइलिश तस्वीर शेयर की जिसमें वह व्हाइट स्लीवलेस टॉप और डेनिम जींस में नजर आ रही हैं। इस फोटो में मोनालिसा ने ओपन हेयर और फ्लोरल इयररिंग्स के साथ अपना लुक कंप्लीट किया है। साथ ही उनकी फिटनेस ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने तस्वीर के कैप्शन में लिखा है – लड़की, तुम्हारे पास पहले से ही वो सब है जो चाहिए। इस पोस्ट के बाद फैन्स उनके आत्मविश्वास और लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कमेंट सेक्शन में हार्ट और फायर इमोजी की बाढ़ आ गई है।

मोनालिसा अपने हर अंदाज़ से फैंस को इम्प्रेस करने में माहिर हैं। कभी ट्रेडिशनल लुक तो कभी वेस्टर्न कैजुअल, उनका हर स्टाइल चर्चा में रहता है। इस लेटेस्ट पोस्ट में उनका सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है। मोनालिसा की यह पोस्ट कुछ ही मिनटों में हजारों लाइक्स बटोर चुकी है और फैन्स उन्हें फैशन आइकन बता रहे हैं। मोनालिसा की सोशल मीडिया पर मजबूत मौजूदगी और उनका आत्मविश्वास भरा अंदाज़ उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से अलग बनाता है।

ब्लैक ड्रेस में तमन्ना भाटिया का हॉट अवतार, फैंस का धड़का दिल

फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित और स्टाइलिश एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में तमन्ना ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें वह एक ब्लैक ड्रेस में नजर आ रही हैं।

इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, दर्शकों को समर्पित एक रात के लिए तैयार जी सिने अवार्ड्स। तमन्ना का यह ब्लैक ड्रेस लुक बेहद स्टाइलिश और बोल्ड है, जो उनके फैंस को आकर्षित कर रहा है। तस्वीर में उनके बालों का सटल और एलिगेंट स्टाइल, साथ ही उनके सॉफ्ट मेकअप ने उनके लुक को और भी शानदार बना दिया। इस पोस्ट पर तमन्ना के फैंस ने ढेरों कमेंट्स और लाइक्स किए हैं।

फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे जैसे मनीष मल्होत्रा, रश्मि तारणजीत, और सोनम बाजवा ने भी इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और तमन्ना की सुंदरता की सराहना की। उनके द्वारा दिए गए कमेंट्स इस पोस्ट को और भी खास बना रहे हैं। तमन्ना भाटिया का यह लुक हर किसी को उनका दीवाना बना रहा है और ज़ी सिने अवार्ड्स के लिए उनका यह खास अवतार फैंस के बीच चर्चा का विषय बन चुका है।

सलमान ने ले लिया अपनी अगली फिल्म पर फैसला, नहीं आ रही बजरंगी भाईजान-2

सलमान खान पिछली बार फिल्म सिकंदर में नजर आए थे, लेकिन न तो उनकी इस फिल्म की कहानी दर्शकों को पसंद आई और ना ही सलमान ने दर्शकों का दिल जीता। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद से सलमान कई निर्माताओं से मुलाकात कर रहे थे और अपनी अगली फिल्म को लेकर बहुत सोच-विचार कर रहे थे।

अब खबर है कि उन्होंने फिल्म को हरी झंडी दे दी है और शूटिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है पिछले 3 महीनों से सलमान अपनी अगली फिल्म के लिए निर्माताओं से बातचीत कर रहे थे। उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट और उनके पनवेल फार्महाउस में खूब चहल-पहल रही। स्क्रिप्ट को लेकर निर्देशकों का सलमान के घर आना-जाना लगा रहा।

अली अब्बास जफर से लेकर राज शांडिल्य, सिद्धार्थ आनंद, राजकुमार पेरियासामी, अनीस बज्मी, कृष आहिर और कबीर खान जैसे निर्देशकों से उनकी बातचीत जारी थी, लेकिन अपूर्व लाखिया की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी सलमान के दिल में घर कर गई।

रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान ने गलवान घाटी 2020 संघर्ष पर आधारित एक वॉर-ड्रामा फिल्म को अपनी अगली फिल्म के रूप में चुन लिया है, जिसे अपूर्व लाखिया निर्देशित करने जा रहे हैं। इस फिल्म में सलमान एक आर्मी अफसर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे।

अभिनेता निर्देशक के साथ इसी साल जुलाई में फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। यह फिल्म लेखक शिव अरूर और राहुल सिंह की किताब इंडियाज मोस्ट फीयरलेस 3 से प्रेरित है। फिल्म को लद्दाख और मुंबई में शूट किया जाएगा। ये 70 दिनों का शेड्यूल होगा।

इसकी कहानी 2 रात की होगी, लेकिन इसे वास्तविक जगहों और सेट पर पूरे 70 दिनों के लिए शूट किया जाएगा। फिल्म में सलमान के साथ युवा पीढ़ी के 3 सितारे नजर आएंगे। निर्देशक ने लोकेशन की रेकी शुरू भी कर दी है। वह चाहते हैं कि फिल्म का बड़ा हिस्सा असल जगहों पर शूट हो, ताकि जनता को बढ़िया सिनेमाई अनुभव दिया जा सके। सलमान निर्देशक कबीर खान के साथ मिलकर बजरंगी भाईजान 2 भी बनाना चाहते हैं. ,लेकिन कबीर इस प्रोजेक्ट से बच रहे हैं।

वह बजरंगी भाईजान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी जगह कबीर ने सलमान को एक ओरिजनल स्क्रिप्ट सुनाई है, जिसमें सलमान का अब तक का सबसे शानदार किरदार होने वाला है, लेकिन अभिनेता ने अभी इस फिल्म के लिए अपनी रजामंदी नहीं दी है।

45 डिग्री तापमान में कमरे की जमीन और दीवारों से निकलता है गरम भपका

रात में सोने के 2 घंटे पहले करें ये 5 काम, मिलेगी बहुत राहत

गर्मी का मौसम अपने चरम पर है। केवल पंखे और कूलर से अब काम नहीं चल रहा । मगर जरूरी नहीं है कि हर घर में एसी हो या हर किसी को ऐसी सूट ही करता हो। ऐसे में पूरा दिन बेशक गर्मी में गुजर जाए मगर रात में सोने से पहले कमरा अगर गरम भपका दे रहा हो, तो रात काटनी मुश्किल हो जाती है। ऐसे बिना एसी के कमरे को ठंडा करना है, तो सोने से 2 घंटे पहले आपको केवल 5 काम करने चाहिए। यदि आप लेख में बताए गए 5 काम कर लेती हैं, तो कमरे की गरम दीवरें और जमीन, दोनों ही ठंडी हो जाएंगी और आप रात में चैन की नींद सो पाएंगी। तो चलिए हम आपको ये आसान तरीके बताते हैं, जिन्हें आप आज ही रात में ट्राई करके देख सकती हैं।

खस की पट्टी (खस कर्टेन) लगाएं

आधुनिकता के चक्कर में हम अपनी पारंपरिक चीजों को भूल चुके हैं। पहले के समय में न एसी होते थे और न ही कूलर। तब लोग अपने घरों को ठंडा रखने के लिए खिड़की और दरवाजों पर खस की घास से बनने पर्दे लगाया करते थे। आज भी आपको गर्मियां आते ही खस के पर्दे जिन्हें खस की टट्टी कहा जाता है। आप इन्हें कमरे के खिड़की और दरवाजों पर लगा लें। रात में सोने के 2 घंटे पहले आप इन्हें पानी से भिगो लें और कमरे का पंखा चला लें। अगर आपके कमरे में कूलर लगा है, तो वो भी चला सकती हैं। बस इस बात का ध्यान रखने कि इतना करने के बाद कमरे को बंद कर दें। ऐसा करने से कमरे की दीवार और जमीन ठंडी हो जाएगी।

लाइट अरेंजमेंट

जितना हो सके आप कमरे में कम से कम लाइट जला कर रखें। खासतौर पर आपको येलो लाइट से बचना चाहिए। इसकी जगह आप ब्लू या व्हाइट लाइट जलाएंगी तो कमरे में उतनी गरमाहट नहीं लगेगी, जितना येलो

लाइट के जलने से लगती है। साथ ही आपको जीरो पावर का बल?ब या ट्यूबलाइट ही जलानी चाहिए, क?योंकि आप पावर यूज करेंगी तो कमरे में ऑटोमैटिकली ही गरमाहट आएगी।

पानी में इस चीज को मिलाकर लगाएं जमीन पर पोछा

जिस कमरे में आप सोने वाली हैं, उसमें आपको 2 घंटे पहले ही पोछा लगाना चाहिए। हो सकते तो पोछा बर्फ के पानी से लगाएं और पानी में नमक जरूर मिला लें। इससे जमीन की गरमाहट खत्म हो जाएगी। जमीन ज्यादा गरम हैं तो आप 2 से 3 बार भी पोछा लगा सकती हैं। पोछा लगाने के बाद आप जमीन पर जूट का बोरा गीला करके बिछा दें। इससे थोड़ी ही देर में कमरी की जमने से निकलने वाला गरम भपका गायब हो जाता है। अगर आप जूट के इन बोरों का इस्तेमाल रोज करती हैं, तो याद रखें कि आपको इन्हें धूप में सुखाना है और समय-समय पर धोना भी है ताकि गंदी स्मेल न आए।

बेड शीट के साथ करें ये काम

वैसे तो आपको यह उपाय बहुत ही क्रेजी सा लगेगा, मगर यह वाकई बहुत अच्छा और असरदार है। गरमी की वजह से बेड पर बिछी बेडशीट तक तपने लगती है। ऐसे में आप रात में सोने से पहले नई बेडशीट बेड पर बिछाएं। इस बेडशीट को बिछाने से पहले एक एयरटाइड पॉलीथीन में रखकर फ्रीजर के अंदर रख दें। इससे वह ठंडी हो जाएगी। फिर आप इसे बेड पर बिछा सकती हैं। इससे आपको ठंडक का अहसास होगा।

सही कूलर प्लेसमेंट

कमरे में अगर कूलर लगा है, तो आपको उसकी सही जगह पर प्लेसमेंट करनी है। खासतौर पर रूम कूलर बहुत ज्यादा ह्युमिडिटी क्रिएट करते हैं। ऐसे में उन्हें हमेशा दरवाजे और खिड़की के पास लगाएं। ऐसा करने से आपको तेज और ठंडी हवा लगें। साथ ही कूलर की घास को गीला करने की जरूरत नहीं है। इससे कमरे में अजीब सी मचलान की महक भर जाएगी।

विष्णु के सुशासन में हो रहा संवाद और समाधान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन में संवाद और समाधान की कड़ी निरंतर रूप से चल रही है। इस सुशासन की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित हर योजना का लाभ हितग्राही को सुनिश्चित कराने हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के मुखिया विष्णु देव साय की पहल पर सुशासन तिहार-2025 का आयोजन प्रदेशभर में किया जा रहा है। शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत से रूबरू होने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार-2025 के तहत आमागोहन समाधान शिविर में पहुंचे और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया।

गौरतलब है कि सुशासन तिहार-2025 के अंतर्गत तीसरे चरण में समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी लेना और स्थानीय समस्याओं का त्वरित निवारण करना है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बिलासपुर के कोटा विकासखंड के आमागोहन गांव पहुंचे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार सुशासन के माध्यम से हर गांव तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। समाधान शिविर के जरिए हम ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका तुरंत समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने राज्य में सरकार बनते ही 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए। हमने महतारी वंदन के तहत माताओं-बहन को आर्थिक सहायता देने का काम किया। प्रदेश में 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। आज महिला सशक्तीकरण का काम महतारी वंदन के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीरामलला दर्शन योजना के जरिए प्रदेश के 22 हजार से ज्यादा लोग श्रीरामलला के दर्शन का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा दर्शन योजना के तहत देशभर के धार्मिक स्थलों में दर्शन की व्यवस्था हमने शुरू की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जो सरकार अच्छा काम करती है, उसी की जनता के बीच जाने की हिम्मत होती है। हम अपने डेढ़ साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। अपने काम का फीडबैक ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई लाभार्थियों को योजनाओं के तहत प्रमाण पत्र और सहायता राशि वितरित की। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

यह शिविर छत्तीसगढ़ सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें ग्रामीण विकास और सुशासन को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी और लोगों की समस्याओं का समाधान होगा।

हितग्राहियों से सीएम साय का सीधा संवाद

आमागोहन समाधान शिविर के दौरान सीएम श्री साय और हितग्राहियों के बीच सीधा संवाद हुआ। इस दौरान ग्रामीण महिला श्रीमती विमला साहू ने बताया कि उन्हें महतारी वंदन के तहत हर महीने एक हजार रुपए मिल रहे हैं, इस पैसे को वो अपने नातिन के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में राशि बैंक में जमा करती हैं। ग्राम मोहली के श्री छोटेलाल बैगा ने बताया कि पहले उनका कच्चा था, जहां बारिश में पानी टपकने से लेकर जहरीले जीव जंतुओं का खतरा हमेशा बना रहता था, अब पीएम आवास बनने से जीवन आसान हुआ है, अब सिर पर छत सुनिश्चित हो गया है। श्रीमती दिलेश्वरी खुसरो ने बताया घर में दो लोगों का आयुष्मान कार्ड बनने से अब उन्हें बीमार होने की स्थिति में किसी तरह की चिंता नहीं रही।

मुख्यमंत्री ने जनहित में घोषणाएं की

मुख्यमंत्री श्री साय ने आमागोहान में समाधान शिविर में बेलगहना में कॉलेज शुरू करने की घोषणा की। वहीं क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए कहा कि आमागोहन में 32 केवी का विद्युत सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा। जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए आमागोहन में एक सामुदायिक भवन की घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों संग किया भोजन

मुख्यमंत्री ग्रामीणों के साथ बैठकर भोजन किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं ग्रामीणों के साथ भोजन करने की मंशा जताई। मुख्यमंत्री के साथ अनीता ध्रुव, कलेशिया बाई, विमला पुरी, छोटेलाल बैगा, दिलेश्वरी खुसरो और अन्य ग्रामीणों के साथ भोजन किया।

मुखिया को हाथों से बनाया स्कैच किया भेंट

एमएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे 24 वर्षीय देव सिंह खुसरो ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को अपने हाथों से बनाया गया पेंसिल स्कैच भेंट किया और कहा कि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय किसान कल्याण की दिशा में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, जिसके लिए उनके परिवार, गांव के लोगों समेत किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

महुआ पेड़ की छांव में सुशासन की चौपाल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बिना पूर्व सूचना के हेलीकॉप्टर से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के बैगा बाहुल्य ग्राम चुकतीपानी पहुंचे। ग्रामीण अपने बीच मुख्यमंत्री श्री साय को यूं अचानक पाकर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन कुछ ही क्षणों में यह हैरानी स्वागत में बदल गई। ग्रामीणों ने गुलमोहर की माला, तेंदू फल की टोकरी और स्थानीय फूल-पत्तियों से बना गुलदस्ता भेंट कर मुख्यमंत्री श्री साय का आत्मीय अभिनंदन किया।

गांव के मिडिल स्कूल परिसर में महुआ पेड़ के नीचे लगी चौपाल में मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीणों से करते हुए कहा कि सरकार कैसे काम कर रही है, यह जानने मैं स्वयं आपके घर आया हूं। जो भी परेशानी है, नि:संकोच बताइए।

चौपाल के दौरान जब मुख्यमंत्री की नजर ओवरफ्लो हो रही पानी टंकी पर पड़ी, तो उन्होंने पानी की बर्बादी पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत पर पीएचई विभाग के सब इंजीनियर को फटकारते हुए कहा कि या तो काम करो, या सस्पेंड होने के लिए तैयार रहो।

जनसंवाद के दौरान महिलाओं ने बताया कि वे महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि से स्व-सहायता समूह बनाकर जैविक खेती कर रही हैं और स्थानीय मंडियों में सब्जियाँ बेचकर आय अर्जित कर रही हैं। उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट से उगाई गई लाल भाजी भी मुख्यमंत्री को भेंट की।

खास खबर

सुरेगांव की राधिका बाई को मिला राशन कार्ड सुशासन तिहार बना ग्रामीणों की उम्मीद का पर्व

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में आयोजित सुशासन तिहार ग्रामीणों के समस्याओं के निदान का सशक्त माध्यम बन चुका है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ग्राम सुरेगांव (जिला बालोद) की राधिका बाई हैं, जिन्हें सुशासन तिहार के पहले चरण में आवेदन के बाद राशन कार्ड प्रदान किया गया है। इस कार्ड के माध्यम से अब राधिका बाई और उनके परिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति माह 35 किलोग्राम नि:शुल्क अनाज प्राप्त होगा।

राधिका बाई ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनके परिवार के लिए राशन कार्ड न होना एक बड़ी समस्या थी। शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने से वे परेशान थीं। लेकिन सुशासन तिहार के समाधान शिविर में जब उन्हें राशन कार्ड सौंपा गया, तो उनकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमें हर माह राशन मिलेगा, जिससे घर का खर्च आसानी से चल सकेगा। यह हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है। राधिका बाई ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने सुशासन तिहार के माध्यम से आम ग्रामीणों की समस्याओं को समझा और समयबद्ध रूप से समाधान सुनिश्चित किया है। राधिका ने राज्य शासन की महतारी वंदन योजना का भी उल्लेख किया, जिसके माध्यम से उन्हें हर महीने एक हजार रूपए की सहायता मिल रही है। उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार 2025 के तहत बालोद जिले में आयोजित समाधान शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को शासन की मूलभूत सेवाओं एवं योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

समाधान शिविर में प्राप्त आवेदनों का विभागीय अधिकारी उत्साह के साथ कर रहे निराकरणः विजय शर्मा

रायपुर। दो दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान रविवार की शाम को उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री विजय शर्मा एवं वनमंत्री केदार कश्यप जगदलपुर के करन्दोला में सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। समाधान शिविर को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का विभागीय अधिकारी उत्साह के साथ कर निराकरण कर रहे हैं। यह आम नागरिकों को तत्काल सुविधा देने की संवेदनशील पहल है। इस दौरान उन्होंने करन्दोला में महतारी सदन के लिए 29 लाख की घोषणा भी की। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार सभी नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। सरकार गांव, ग्रामीणों की समस्या को समझती है, गांवों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखती है, इसलिए सुशासन तिहार का कार्यक्रम संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि आमजनों द्वारा दी गई आवेदनों पर विभागों के द्वारा तत्काल कार्यवाही की जा रही है। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप ने भी संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन तिहार, समाधान शिविर में आवेदन पर विभागीय अधिकारी तत्काल निराकरण कर रहे है इसका जरूर लाभ लें। कार्यक्रम में मेघावी छात्रों को सम्मानित किया गया साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र, आवास की स्वीकृति आदेश पत्र, दिव्यांगजनों को ट्राई सायकल, किसानों को बीज वितरण भी किए।

विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन 29 मई से 12 जून 2025 तक

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन 29 मई से 12 जून 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। इस संबंध में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज नई दिल्ली से राष्ट्रीय स्तर पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ प्रदेश से राज्य के कृषि मंत्री राम विचार नेताम शामिल हुए।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ''लैब टू लैंड'' मंत्र को साकार करने के दिशा में एक बढ़ा कदम है, जो एक देश, एक कृषि, एक टीम की अवधारणा को मजबूती देगा। यह अभियान भारतीय कृषि अनुशंधान संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी, प्रगतिशील कृषक, एफ्पीओ आदि के सहयोग से ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य को संपादित करेंगा। इसका उद्देश्य आधुनिक, उन्नत, आदर्श और प्राकृतिक खेती को बढावा देना तथा किसानों को वैज्ञानिक जानकारी और सहकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। साथ ही किसानों द्वारा दिये गये सुझाव पर अमल करते हुए वैज्ञानिकों द्वारा इसे शोध में शामिल कर नवीन दिशा निर्धारित करना है। वैज्ञानिकों की टीम एग्रोक्लायमेटिक जोन, को ध्यान रखते हुए खरीफमौसम की प्रमुख फसलों से संबधित आधुनिक तकनिकों के बारे में किसानों को जागरूक करेगी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार संतुलित उर्वरक उपयोग की सलाह देगी, ड्रोन तकनीक, धान की सीधी बुआई जैसी तकनीको का प्रदर्शन किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री नेताम ने केन्द्र सरकार के अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त 33 जिलों में चलाया जाएगा। जिसमें कुल 99 दल द्वारा 2,772 स्थान पर कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर अभियान के सफलतापूर्वक संपादन के लिए जिला उप संचालक कृषि को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री नेताम ने बताया कि राज्य स्तर पर संचालनालय कृषि में एवं जिला स्तर पर उप संचालक कृषि कार्यालय में इस अभियान के निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है। जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं कृषि विभाग से संबंध विभाग के समन्वय से कार्य करेंगे। जिलों के प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि सहित राज्य और जिला के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहेंगे।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ शासन की कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, संचालक कृषि राहुल देव, संचालक उद्यानिकी जगदीश एस., संचालक पशुपालन चन्द्रकांत वर्मा, संचालक मत्स्यपालन नारायण सिंह नाग, निदेशक विस्तार, अनुसंधान सेंवाएं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉ. अनिल टुटेजा एवं डॉ. विवेक त्रिपाठी, उप सचिव कृषि विभाग विकास मिश्रा एवं नोडल अधिकारी बी. के. मिश्रा उपस्थित थे।

सुशासन तिहार में कृषक बदलू के आवेदन का हुआ त्वरित निराकरण

मुख्यमंत्री की संवेदनशील पहल से जनता को मिल रहा सीधा लाभ, सुशासन तिहार लाया है खुशियों की सौगात

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल पर प्रदेशभर में आयोजित सुशासन तिहार आम लोगों के लिए समस्याओं के समाधान और मांगों के निराकरण का सशक्त माध्यम बना है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले में आयोजित समाधान शिविर में कृषक श्री बदलू के आवेदन का त्वरित निराकरण कर उन्हें 'कृषक पुस्तिका' प्रदान की गई।

कृषक बदलू को इस किताब में कृषि भूमि, फसल और सरकारी योजनाओं के लाभ की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें अब अपने भूमि संबंधी दस्तावेज़ों के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार द्वारा आयोजित सुशासन तिहार का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक की समस्याएं पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ सुनी और सुलझाई जाएं। कृषक श्री बदलू के मामले में जिला प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता देखने को मिली है।

कृषक बदलू ने किसान किताब' प्राप्त कर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि, अब मेरे पास मेरी जमीन और फसल से जुड़ी सारी जानकारी एक जगह सुरक्षित है। इससे मुझे बहुत सहूलियत मिलेगी। मैं सुशासन तिहार के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं। सुशासन तिहार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनभागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता को साकार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह तिहार न्याय, अधिकार और समाधान की नई परंपरा स्थापित कर रही है।

सुशासन तिहार न केवल समस्याओं के निराकरण का माध्यम बन रहा है, बल्कि यह जनता के चेहरे पर मुस्कान और भरोसे की बहाली का भी प्रतीक बनकर उभरा है।

कृषक बदलू जैसे लाभार्थी इस बात का प्रमाण हैं कि जब शासन योजनाओं के क्रियान्वयन में संवेदनशील होता है, तब सुशासन जन-जन तक पहुंचता है।

सीईओ जिला पंचायत ने जनदर्शन में सुनी आम नागरिकों की शिकायतें

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशन में सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग ने जनदर्शन में आम नागरिकों की समस्याओं को सुना। उन्होंने जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर निश्चित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में कुल 97 आवेदन प्राप्त हुए।

कलेक्टर जनदर्शन में जाति प्रमाण पत्र,पेंशन, राशनकार्ड, वनअधिकार पत्र, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन,बंटवारा आदि आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन में ग्राम पंचायत कोरबी के मनोज कुमार ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण की मांग की। बताती निवासी अमरसिंह ने अपनी पुस्तैनी जमीन में बंटवारे और पर्ची अलग करने का आवेदन लगाया। ग्राम खमरिया पाली के अभिषेक भारद्वाज ने वर्ष 2024 में अतिवृष्टि के मुआवजा की मांग की। पाली के ग्रामीणों ने वन अधिकार पत्र के वितरण की मांग की। पाली के ही रामनाथ र्णार ने राजस्व रिकॉर्ड सुधारने का आवेदन दिया। बांसाखर्रा,गेराव के ग्रामीणों ने विशेष पिछड़ी जन जाति बिरहोर बस्ती में छिंदवारपारा में बिजली कनेक्शन तथा ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। बालको नगर की रहने वाली देव कुमारी महंत ने प्रधानमंत्री आवास का आवेदन दिया। सीईओ जिला पंचायत ने संबंधित अधिकारियों को प्रकरण प्रेषित कर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

शासन की योजनाओं से आम जनता के जीवन में आ रहा आमूलचूल परिवर्तन : संतोष पाण्डेय

श्रीकंचनपथ न्यूज

राजनांदगांव। सांसद संतोष पाण्डेय सुशासन तिहार अंतर्गत जनपद पंचायत छुरिया के ग्राम खोभा में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि सुशासन तिहार अंतर्गत समाधान शिविरों में विभागीय स्टॉलों में जनसामान्य की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है और साथ ही उनकी जिज्ञासाओं का भी समाधान हो रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बहुआयामी विकास कार्य हो रहे है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनमानस के जीवन स्तर के उन्नयन के लिए बुनियादी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। हर व्यक्ति का यह सपना होता है कि उसका अपना पक्का आवास हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 18 लाख पक्के मकान की स्वीकृति मिली है। इसी तरह ग्राम खोभा में 203 आवास स्वीकृत किए गए है। शासन की योजनाओं से आम जनता के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। जिले में 98 प्रतिशत संस्थागत प्रसव बढ़ा है तथा मातृ मृत्यु दर में कमी आयी है। सरकार कृषकों के साथ ही सभी वर्ग के नागरिकों के विकास के लिए तेज गति से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज हम तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे है। जम्मू-कश्मीर के पहलगांव में आंतकवादियों ने निर्दोष नागरिकों की हत्या की। इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने आंतकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके आतंकी स्थानों को ध्वस्त किया। भारतीय सेना के सम्मान में हम सभी आज तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे है। इस अवसर पर सांसद संतोष पाण्डेय तिरंगा यात्रा में शामिल हुए।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव ने कहा कि समाधान शिविर में जनता के शिकायतों के निराकरण के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है और शासन-प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंच रही है। सुशासन तिहार का प्रभाव अब नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना सहित विभिन्न योजनाओं से जनसामान्य लाभान्वित हो रहे है। प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्के आवास का सपना पूरा हो रहा है। वही शासन की जनधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ नागरिकों को मिल रहा है। सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नन्हें शिशुओं का अन्नप्राशन्न कराया गया तथा गर्भवती माताओं की गोदभराई की गई। उन्होंने हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया। साथ ही विभागीय स्टालों का अवकलोकन कर पात्र हितग्राहियों एवं योजनाओं के संबंध में जानकारी ली।

CAR DECOR
House Of Exclusive
Seat Cover,
Car Stereos Matting &
Sun Control Film &
Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower.
Opp. Indian Coffee House,
Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM
Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES
FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden)
Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेनेक्स एवं ग्रहलन उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles,
CPVC Pipes &
Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

अपराधी नंदकुमार जिला बदर, कलेक्टर ने की कार्रवाई

राजनांदगांव। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के आदतन अपराधी नंदकुमार साहू को जिला बदर किया गया है। वह बुधवारी पारा वार्ड नंबर 15 का रहने वाला है। नंदकुमार साल 2013 से मारपीट, आगजनी, अवैध शराब बिक्री और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में लगातार संलिप्त रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ प्रतिवेदन तैयार कर जिला दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला दंडाधिकारी ने आदेश में एमव सीजी राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 और 5 के तहत कार्रवाई की गई। नंदकुमार को राजनांदगांव सहित सरहदी जिलों से तीन माह के लिए हट जाने का आदेश दिया गया है।

आकाशीय बिजली गिरने से दंपत्ति की दर्दनाक मौत

कवर्धा। कवर्धा जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किसान और उसकी पत्नी की मौत हो गई। सिंगापुर गांव में प्याज की फसल को बारिश से बचने के लिए दोनों खेत में तिरपाल लगाने गए थे। इस दौरान बिजली गिर गई। मामला पंडरिया थाना क्षेत्र का है। घटना 18 मई रविवार की है। आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे लेकिन गणेश पटेल (40) और मीरा पटेल (36) की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिजनों में शोक है। गणेश ने अपने खेत में प्याज की फसल लगाई थी। अचानक मौसम बदला। आंधी और गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। बेमौसम हो रही बारिश से प्याज की फसल खराब हो सकती थी। जिससे किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ फसल बचाने पहुंचा था। जानकारी मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की। पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

भालू के हमले से महिला की मौत

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में वन्यजीव और मानव संघर्ष का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत चिकनी, पोस्ट लांजीत क्षेत्र में भालू के हमले में एक महिला की मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह 7 से 8 बजे के बीच की है। फूलमती सिंह धुर्वे (32) तेंदूपत्ता तोड़ने जंगल गई थी। इसी दौरान एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। उसने वहीं दम तोड़ दिया। जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश है। ग्रामीण वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि वन विभाग और प्रशासन को इस समस्या के समाधान के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए। वहीं, फूलमती के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग किए है। फूलमती की असमय मौत से उनके परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है।

25 ट्राफिक वार्डन रायपुर शहर की सड़कों पर किए जाएंगे तैनात

शहर में लगातार वाहनों के बढ़ने से सभी चौक-चौराहों में यातायात का बढ़ रहा दबाव

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। आईजी अमेरश मिश्रा द्वारा गौरव सिंह, कलेक्टर रायपुर, लाल उमेद सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर, विश्वदीपक आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर, विश्वरंजन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर, प्रशांत शुक्ला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर एवं गुरजीत सिंह, सतीष ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर की उपस्थिति में 25 ट्राफिक वार्डन को रायपुर शहर के जाम लगने वाले स्थानों-चौक-चौराहों पर कार्य पर लगाने हेतु नियुक्त किया गया।

ट्राफिक वार्डन एक नई पहल कार्यक्रम में नगर निगम के टीम प्रहरी के पुरूष एवं महिला स्टाफ यातायात के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा 25 नये ट्राफिक वार्डन सहित 200 लोग उपस्थित थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि रायपुर शहर में लगातार वाहनों के बढ़ने से सभी चौक चौराहों में यातायात का दबाव बढ़ रहा है। बाजार क्षेत्रों में सड़क किनारें वाहनों की पार्किंग से अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। नगर निगम के टीम प्रहरी पुलिस के साथ संयुक्त रूप से सड़कों को आवागमन के लिए उपलब्ध कराने अतिक्रमण पर कार्यवाही प्रभावी तरीके से कर रही है। यातायात बल में कमीं होने से सभी जंक्शन स्थानों पर ड्यूटी नही लग पा रही है जिसकी पूर्ति होती पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज के निर्देशन में जिला प्रशासन, नगर निगम, जिला पंचायत एवं रायपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 25 ट्राफिक वार्डन नियुक्ति किया गया है। नियुक्त हुए ट्राफिक वार्डनों को कलेक्टर दर पर देय निर्धारित मानदेय प्रदाय किया जाएगा।

सभी को चौक चौराहों पर यातायात व्यवस्था संभालने संबंधी प्रशिक्षण उपरांत फिल्ड पर जाम लगने वाले स्थानों पर कार्य पर लगाया जाएगा। गौरव सिंह कलेक्टर रायपुर एवं विश्वदीप आयुक्त नगर पालिक निगम ने अपने संबोधन में कहा कि आपकी नियुक्ति अस्थायी रूप से की जा रही है। 01 माह उपरांत आपके कार्यो के परफार्मेंस की समीक्षा की जाएगी। जिस तरह अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में टीम प्रहरी के कार्यो की प्रशंसा जनता करती है इसी तरह भी आपकी उपस्थिति एवं कार्यो से व्यवस्था में बदलाव दिखे, जाम से लोगों को निजात मिलें और जनता आपके कार्यो की प्रशंसा करे ऐसा उद्देश्य लेकर आपको कार्य करना है। कार्य के दौरान लोगों के साथ अपना विनम्र व्यवहार रखना है, किसी से वाद-विवाद की स्थिति निर्मित न करते हुए ईमानदारी से आपको कार्य करना है, आपके कार्यो से जिला प्रशासन की छबि जुड़ी हुई है। शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने की दिशा में प्रशासन चिंतित है। जो संसाधन की आवश्यकता होगी वह भी उपलब्ध कराया जाएगा।

अमरेश मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत देश में गुजरात में सबसे पहले ट्राफिक वार्डन को पुलिस का हिस्सा बनाकर पुलिस के कार्यो में शामिल किया गया । छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायपुर में यह शुरूआत की जा रही है आपके कार्यो के रिपोर्ट के आधार पर अन्य जिलों में भी आवश्यकतानुसार ट्रैफिक वार्डन योजना को शुरू किये जाने की पहल की जा सकती है। आपको पुलिस विभाग के बल की तरह अधिकार प्राप्त नही होगा आपका उत्तरदायित्व होगा कि आपको जिस जगह पर यातायात व्यवस्था बनाने के लिए कार्य पर लगाया जाता है उस जगह को सुगम बनाए। व्यवस्था बनाने के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई हो, कोई सुधार की आवश्यकता हो, कोई बात नही सुनता हो, कोई सुझाव हो या कोई ऐसी गतिविधि जो कानूनन अपराध हो यह दिखाई देता है तो उसकी सूचना भी थाना प्रभारी या प्रशासनिक अधिकारियों को दें जिससे वह कार्य कराया जा सके। जिला रायपुर में ट्राफिक वार्डन का नई पहल है आपको रोल मॉडल बनना है। आपकी सेवा से विभाग को अच्छी पहचान मिले ताकि आपके अच्छे भविष्य के लिए सरकार से बात किया जा सके। अंत में सभी नवनियुक्त 25 वार्डन को ट्राफिक में बेहतर कार्य कर अपनी पहचान बनाने की अग्रीम बधाई देते हुए नगर निगम के टीम प्रहरी को उनके योगदान के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देकर शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने कहकर कार्यक्रम समाप्त किया।

पैसे के अभाव में घायलों की नहीं होगी मौत

सड़क दुर्घटना के घायलों का पहले 7 दिन हर अस्पताल को नगदी रहित (कैश लेस)इलाज करना अनिवार्य है। यह इलाज स्वास्थ्य विभाग से मान्यता प्राप्त प्रदेश के 134 और राज्य के बाहर के सभी 61 अस्पतालों को करना होगा। यानी किसी अन्य राज्य में प्रवास पर जाने के दौरान दुर्घटना होने पर वहां भी कैश लेस इलाज हो सकेगा। सड़क सुरक्षा के लिए पीएचक्यू मे गठित अंतरविभागीय लीड एजेंसी मे सभी कलेक्टर,पुलिस अधीक्षकों को कल ही यह पत्र जारी किया है। भारत सरकार के राजपत्र में, 5 मई को प्रकाशित नगदी रहित उपचार स्कीम 2025 अधिसूचना के हवाले से राज्य एजेंसी ने यह आदेश जारी किया है। यह कैश लेस इलाज, दुर्घटना के बाद पहले 7 दिन तक 1.50 लाख रूपए तक हो सकेगा। बता दें कि सरकार की इस पहल से पैसे के अभाव में घायलों की मौत हो होगी।

आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, महुआ शराब और 1800 किलो लहान किया जप्त, चार गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। आबकारी विभाग की टीम ने बिल्हा और बोदरी बड़ी कार्रवाई की है। बोदरी में जहां 250 लीटर महुआ शराब जप्त की है वहीं 1790 किलो महुआ लगान जप्त किया है। टिम ने अवैध शराब बनाने और बेचने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

कलेक्टर बिलासपुर संजय अग्रवाल के निर्देश और प्र. सहायक आयुक्त आबकारी जिला बिलासपुर नवनीत तिवारी के मार्गदर्शन में बोदरी और चकरभाटा क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी टिम ने कच्ची शराब विक्रेताओं से 250 लीटर कच्ची शराब ज़ब्त किया है और 1790 किलोग्राम महुआ लाहन तालाब एवं नाले से बरामद कर मौक़े पर ही नष्ट किया गया है।

जानकारी के अनुसार टिम ने बोदरी के वार्ड नंबर 9 निवासी नागेंद्र वर्मा पिता नानकु वर्मा से 25 लीटर, राजेश पिता झुनाऊ वर्मा से 35 लीटर, रवि पिता राजकुमार वर्मा से 40 लीटर, संतु पिता दर्शन प्रसाद वर्मा से 15 लीटर महुआ शराब और 45 किलोग्राम महुआ लहान जप्त किया है। इसके अलावा बोदरी के नउआ तालाब से 75 लीटर महुआ शराब एवं 1525 कि महुआ लहान जप्त किया है। तालाब के पास एक नाले भी 60 लीटर महुआ शराब और 220 किलोग्राम महुआ लहान बरामद किया है। मामले में आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) 59(क) का प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिया है। कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी कल्पना राठौर बिल्हा क्षेत्र प्रभारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी छबि पटेल, आबकारी उप निरीक्षक भूपेंद्र जामरे, ?श्वर्या मिंज, मुख्य आरक्षक अनिल पांडे, जयशंकर कमलेश, कल्याण कहरा, वीरभद्र जायसवाल आरक्षक श्रीकांत राठौर, प्रभुवन बघेल एवं ड्राईवर संदीप खलखो, जितेन्द्र शर्मा शामिल थे।

8 साल के मासूम लड़के से किया अप्राकृतिक कृत्य, गला घोंटकर कर दी हत्या

श्रीकंचनपथ न्यूज

कांकेर। कांकेर में एक नाबालिग लड़के ने 8 साल के लड़के को हवस का शिकार बनाया। फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि नाबालिग पोर्न वीडियो देखने का आदी था। वारदात के समय नशे की हालत में भी था। मामला चारामा थाना इलाके का है। मृतक हरेश कक्षा तीसरी का छात्र था।

शनिवार शाम 4:30 बजे से लापता था। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि हरेश को आखिरी बार गांव के एक नाबालिग के साथ देखा गया था। जांच में पता चला कि, नाबालिग आरोपी ने शनिवार (18 मई) को एक दुकान से फ्रूटी खरीदी और हरेश को पिलाने के बहाने पहाड़ ले गया। यहीं उसने वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस ने सोमवार सुबह उस नाबालिग से पूछताछ की। पूछताछ में उसने हरेश की हत्या करना स्वीकार कर लिया। नाबालिग ने बताया कि, उसने गलत काम करने के बाद किसी को बता देने के डर से चाबी में लगे पट्टे से बच्चे का गला घोंट दिया। इसके बाद उसके शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया। पुलिस ने ग्राम सरपंच और ग्रामीणों के साथ गड़िया पहाड़ से शव बरामद किया है। ग्राम लखनपुरी के गड़िया पहाड़ में बच्चे की लाश अर्धनग्न हालत में मिली है। इस इलाके में कम लोग जाते हैं। दो दिन पुराना होने के कारण शव से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ से एक से ज्यादा आरोपियों के शामिल होने की भी आशंका है। हत्या के कारणों की जांच जारी है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।

शराब दुकान में चोरों का धावा: लाखों की शराब और नकदी लेकर फरार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मांढर विधानसभा क्षेत्र में चोरी और डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। शनिवार की रात एक बार फिर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मांढर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में घुसकर चोर 1.30 लाख रुपये की शराब और 70 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए। घटना के बाद विधानसभा थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच जांच में जुट गई है, लेकिन 24 घंटे बाद भी चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

गौरतलब है कि शराब दुकान की सुरक्षा के लिए दो सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। इसके बावजूद इतनी बड़ी चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। जानकारी के अनुसार, चोर दुकान के पीछे की दीवार में छेद कर अंदर घुसे और जम्मू ब्रांड की 24 पेटी शराब, महंगी शराब की बोतलें और दराज में रखे नगद रुपए चुरा ले गए। चोरी की घटना का पता रविवार सुबह तब चला, जब कर्मचारी दुकान खोलने पहुंचे। शुरुआती जांच में संदेह जताया जा रहा है कि चोरों ने वारदात से पहले पूरी दुकान की रेकी की थी। उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की लोकेशन और ड्यूटी का पूरा अंदाजा था। बताया जा रहा है कि घटना की रात मांढर स्टेशन बस्ती और देसी शराब दुकान की बिजली भी गुल थी, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया।

शराब दुकान के अंदर सीसी टीवी कैमरे लगे थे, लेकिन बिजली बंद होने के कारण कैमरे काम नहीं कर पाए और चोरी की घटना रिकॉर्ड नहीं हो सकी। इस वजह से पुलिस को जांच में और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मांढर में यह पहली घटना नहीं है। एक सप्ताह पहले वार्ड क्रमांक 5 में पंच वीरेंद्र घिवडोंडे के घर में दिनदहाड़े चोरी हुई थी। चोर सोने-चांदी के जेवरात और 13,000 रुपये नकद सहित करीब 90,000 रुपये की संपत्ति चुरा ले गए थे। उस मामले में भी पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

राज्य के विभिन्न जिलों के 331 मेडिकल स्टोर में की गई छापामार कार्रवाई, 21 प्रतिष्ठानों में नियमों का उल्लंघन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आम लोगों को सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की सख्ती जारी है। औषधियों की कीमतों पर नियंत्रण और निगरानी के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 331 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 21 प्रतिष्ठानों में निर्धारित मूल्य का उल्लंघन पाया गया, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के निर्देश पर राज्य में कार्यरत मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (CGPMRU) द्वारा की गई।

सीजीपीएमआरयू के नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन को आवश्यक औषधियां निर्धारित कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएं। इसी उद्देश्य से भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्यरत एनपीपीए द्वारा 24 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ में मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (CGPMRU) की स्थापना की गई थी। यह इकाई ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करते हुए प्रदेश में अधिसूचित औषधियों की कीमतों पर सतत निगरानी रखती है। सीजीपीएमआरयू, एनपीपीए की प्रमुख सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करते हुए राज्य के विभिन्न औषधि प्रतिष्ठानों से जमीनी स्तर पर जानकारी एकत्र कर नियामक अनुपालन सुनिश्चित कर रही है।

सीजीपीएमआरयू के नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कुल 331 औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 21 प्रतिष्ठानों में अधिसूचित मूल्य का उल्लंघन पाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इन सभी मामलों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, नई दिल्ली के आईपीडीएमएस पोर्टल पर दर्ज कर लिया गया है। संबंधित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एनपीपीए देशभर में राज्य स्तरीय निगरानी इकाइयों के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभा रहा है। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएमआरयू की यह पहल प्रदेशवासियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

एसडीएम ने अवैध नाका को किया सील, ग्रामीणों का हंगामा

जगदलपुर। जगदलपुर में स्थित सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चित्रकोट पर सोमवार को बवाल मच गया। लोहंडीगुड़ा एसडीएम नीतीश वर्मा ने समिति द्वारा संचालित नाका को अवैध बताते हुए सील कर दिया। दरअसल, गांव के लोगों की एक समिति इस नाके का संचालन करती है। चित्रकोट पर्यटन स्थल घूमने आने वाले पर्यटकों से वाहन प्रवेश और पार्किंग के नाम पर समिति लंबे समय से शुल्क वसूलता आ रहा है। एसडीएम ने उक्त समिति को अवैध करार देते हुए नाका को ही सील कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित नाका समिति ने गांव के सरपंच भंवर मौर्य के नेतृत्व में मारडूम चौक में चित्रकोट मार्ग को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरपंच भंवर मौर्य का कहना है कि मार्च महीने में ही ग्राम सभा कर नई समिति को नाका की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि पुरानी समिति द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया। पुरानी समिति पर कोई कार्यवाही न करते हुए नई समिति के काम पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया। सरपंच मौर्य ने लोहंडीगुड़ा एसडीएम के मेहमानों के लिए उचित व्यवस्था समिति द्वारा नहीं किए जाने के चलते यह कार्यवाही करने का आरोप लगाया। तकरीबन 5 घंटे तक समिति के सदस्य कड़ी धूप में सड़क के बीचोबीच प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे।

भिलाई की सबसे बड़ी
चुड़ी की दुकान
निखार बैंगल
मो.- 9826186026
Shop-47, 'A' Market, Sec-6, Bhilai Nagar, Distt., Durg (C.G.)

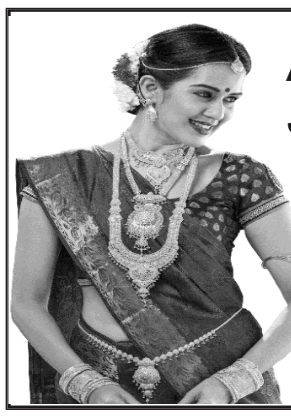
Ashok JEWELLERY
Gifts • Toys • Cosmetics
Perfumes • Sia Jewellery
Beside Parakh Jewellers, Akash Ganga, Supela, Bhilai
Hello: 0788-4052727
Mukesh Jain 9009959111
Rishabh Jain 8103831329

राकेश ट्रेडर्स
राकेश ट्रेडर्स जो चर्च के पास था वह आगे चला गया है पिछले दस वर्षो से
Dealers
Marbles, Grinight, Black Stone, Nano & Double Charge Verified Tiles Digital Wall & Floor Tiles Cement Coloru etc.

रायपुर रेट पर माल उपलब्ध | Rakesh Sahu 9302443750, 9907127357
Krishna Talkies Road, Beside Swami Aatmanad School, Risali, Bhilai - 490006

भिलाई मसाला उद्योग

शुद्ध कुटे हुए मसाले,पापड़, अचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, जचकी का सामान इत्यादि
128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, फोन. 2284508, मो. 9826137766

जो सरकार अच्छा काम करती है वह आम जनता के बीच जाने से नहीं कतराती : मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का उड़न खटोला बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम आमागोहन में उतरा। वनांचल के आदिवासी ग्राम में मुख्यमंत्री श्री साय को अपने बीच पाकर ग्रामीणों में उत्साह और खुशी का माहौल था। वे चिलचिलाती धूप की परवाह किए बगैर अपने राज्य के मुखिया को एक झलक देखने और उन्हें सुनने के लिए घण्टो डटे रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने समाधान शिविर में जहाँ ग्रामीणों से संवाद किया वहीं मुख्यमंत्री ने समाधान पेटी में डाले गए आवेदनों की निराकरण की स्थिति भी जानी। उन्होंने सुशासन तिहार की सार्थकता को बताते हुए कहा कि आज सुशासन तिहार के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सरकार आपके गाँव में आई है। हमने बीते डेढ़ वर्षों में राज्य के लोगों के हित में कार्य किया है। जो सरकार अच्छा काम करती है उनकी ही हिम्मत होती है जनता के बीच जाने की। सुशासन तिहार एक तरह से हमारा रिपोर्ट कार्ड भी है और हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का आंकलन करने का अवसर भी। इसके माध्यम से सरकार योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति भी जान रही है।

दसवीं-बारहवीं के मेधावी बच्चों को सम्मानित कर किया प्रोत्साहित, दी शुभकामनाएं

आमागोहन के समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने 10वी-12वी बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने दसवीं में 90 प्रतिशत अंक हासिल करने वाली महिमा पटेल, स्नेहा सेन, बारहवीं की वर्षा पाण्डेय को सम्मानित कर उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी।

शासन की योजनाओं से जीवन में आया बदलाव

समाधान शिविर में पीएम आवास, महतारी वंदन योजना, पीएम सम्मान निधि के किसानों ने योजना का लाभ उठाकर जीवन में आए बदलाव को बयां किया। पीएम आवास की हितग्राही छोटे लाल ने बताया कि पहले वे खपरैल वाले मिट्टी के घर में रहते थे। इससे साँप,बिच्छु का खतरा बना रहता था। अब पक्का मकान बनने से बारिश के दिनों में होने वाली समस्या दूर हो गई है। महतारी वंदन योजना की हितग्राही श्रीमती विमला बाई पुरी ने बताया कि उन्हें मार्च 2024 से महतारी वन्दन योजना से हर महीने एक हजार रुपये मिलते हैं। इस राशि का उपयोग उन्होंने अपनी नतनी वामिका पुरी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में किया है ताकि भविष्य में इस राशि का उपयोग पढ़ाई के लिए हो सके। पीएम जनमन अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही दिलेशरी खुसरो ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका आयुषमान कार्ड बना है। इससे 5 लाख तक का उपचार हो पायेगा।

2265 में 2212 आवेदन का किया गया निराकरण

समाधान शिविर आमागोहन क्लस्टर में कुल 2265 आवेदन प्राप्त हुए,जिसमे से 2212 का निराकरण कर दिया गया है। इस क्लस्टर में 11 गाँव आमागोहन, सोनपुरी, तुलुप,नगोई, नवगांव सोनसाय,मोहली, खोंगसरा, डाँड़बछाली, टांटीधार, बिटकुली शामिल है।

सुशासन तिहार के तीसरे चरण के तहत बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के अंतर्गत दूरस्थ आदिवासी ग्राम आमागोहन के समाधान शिविर में मुख्यमंत्री श्री साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से राज्य में हमारी सरकार बनी और डेढ़ वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में लोकसभा,नगरीय निकाय,नगर पंचायत में हमारी सरकार बनी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत किए गए सभी वादों को पूरा किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शपथ लेते ही अगले दिन से 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने दुर्ग और अम्बिकापुर में भी राज्यवासियों को 3-3 लाख पीएम आवास दिये। इसके अलावा पीएम जनमन आवास और नक्सल क्षेत्रों में आत्म समर्पित परिवारों को आवास दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवास प्लस में जिनका नाम है उनको भी आवास दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों का वादा पूरा कर 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का निर्णय लिया। दो वर्ष से बकाया धान बोनस राशि भी दी। उन्होंने कहा कि 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वन्दन योजना की राशि उनके खाते में देकर आर्थिक समृद्धि और महिला सशक्तिकरण का द्वार खोला। जिनका नाम छूट गया है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है,आने वाले दिनों में छूटे हुए हितग्राहियों का नाम भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले हितग्राहियों के हित में निर्णय लेते हुए प्रति मानक बोरा की राशि 4 हजार से 5500 रुपये किया गया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही रामलला दर्शन योजना प्रारंभ कर हितग्राहियों को रामलला का दर्शन कराया है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने बड़े-बुजुर्गों की इच्छाओं को पूरा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को प्रारंभ किया है। इस योजना से तीर्थ यात्रा के इच्छुक परिवार अन्य तीर्थ स्थल का लाभ उठा पाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 24 अप्रैल से ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ की है। इस योजना से सभी ग्राम पंचायत जुड़ेंगे और ग्रामीणों को गाँव में ही बैंक जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र में किसी भी योजना के हितग्राहियों को राशि निकालने में सुविधा होगी। वही जाति, निवास सहित अन्य दस्तावेज भी मिल पाएंगे। अभी 1460 पंचायत में यह प्रारंभ की गई है। इससे ग्रामीणों को बैंक तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के साथ कार्यवाही भी कर रही है। उन्होंने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री के साथ सरकार ने नामांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इससे कोई अधिकारी नामान्तरण के नाम पर किसी को घुमा नहीं पायेगा। एक घण्टे से कम समय में नामांतरण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा करने वाली यह सरकार सुशासन की दिशा में कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानन्द, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सुर्यवंशी,कलेक्टर, एसपी आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आमागोहन के समाधान शिविर में आई मांग को ध्यान रखकर बेलगहना में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने आमागोहन सहित आसपास के ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए 33 केव्ही का विद्युत सब स्टेशन और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की।

समाधान शिविर में पहुँचे बिलासपुर सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन लाल साहू ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से प्रदेश के कोने-कोने में शिविर का आयोजन कर आवेदन लिए गए। मुख्यमंत्री जी हर छोटे छोटे गाँव में जा रहे हैं। गाँव की समस्याओं का निराकरण भी हो रहा है। यह सौभाग्य है कि सुशासन तिहार के अंतर्गत वे बिलासपुर जिले के अंतिम छोर के आदिवासी क्षेत्र के गाँव आमागोहन आये। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के कुछ दिनों के भीतर ही मोदी की गारंटी को पूरा किया गया है। अब वे योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेने गाँव-गांव जा रहे हैं। उन्होंने बेलगहना में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज,आमागोहन में विद्युत सब स्टेशन सहित अन्य मांग भी रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम आवास के हितग्राही छतौनी लाल,नरबदिया बाई,समरीत बाई को आवास की चाबी सौंपी। उन्होंने बिहान के महिला समूहों, सहकारिता, उद्यान,राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हितग्राहियों को सामग्री और राशि का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री को छात्र दीपिका और देवी सिंह खुसरो ने हाथ से बनाई मुख्यमंत्री की पोट्रेट भी भेंट की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया मुंगेली में नवनिर्मित जिला परिवहन कार्यालय का लोकार्पण

लाइसेंस और पंजीयन संबंधी कार्यों में आमजन को मिलेगी बड़ी सुविधा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के ग्राम बछेरा में 1 करोड़ 72 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जिले में स्थायी परिवहन कार्यालय भवन की सुविधा का अभाव था, जिससे आम नागरिकों को लाइसेंस, वाहन पंजीयन और अन्य कार्यों में कठिनाई होती थी। अब नए भवन के साथ यह सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी, जिससे जनता को काफी राहत मिलेगी।

लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री ने पांच आवेदकों को प्रतीक स्वरूप लर्निंग लाइसेंस प्रदान किए, जिससे उनके चेहरे पर खुशी झलक उठी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता जनता को समयबद्ध और सुगम सेवाएँ उपलब्ध कराना है। नये कार्यालय भवन के माध्यम से वाहन पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी प्रमुख सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी।

छह एकड़ भूमि में निर्मित इस परिसर में एक एकड़ में कार्यालय भवन तथा पाँच एकड़ क्षेत्र ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस टेस्टिंग सेंटर के लिए आरक्षित रखा गया है। भवन में 18 कक्ष, 6 हॉल, अटैच लेट-बाथ तथा सामान्य शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कार्यालय को पूर्णतः सुविधायुक्त रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे विभागीय कार्यों की दक्षता भी बढ़ेगी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 से अब तक जिले में 11,721 ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा चुके हैं और 49,000 से अधिक वाहनों का पंजीयन हो चुका है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि लोगों में परिवहन सेवाओं की बड़ी मांग है, जिसे यह नया कार्यालय सुगमता से पूरा करेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में विकास को गति देने के साथ-साथ प्रशासनिक दक्षता और सेवा-सुलभता को बढ़ाना हमारी सरकार का सतत प्रयास है।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक पुन्नूलाल मोहले, धरमलाल कौशिक, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद सहित अन्य अधिकारीगण तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित थे ।

मुख्यमंत्री साय ने किया मुंगेली में सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क और उन्नत पुलिस कंट्रोल रूम का लोकार्पण

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुंगेली जिला मुख्यालय में स्मार्ट सुरक्षा प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 33.15 लाख रुपये की लागत से तैयार अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क और उन्नत पुलिस कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया।

नगर के 17 प्रमुख चौक-चौराहों पर कुल 62 अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिन्हें एक केंद्रीकृत पुलिस कंट्रोल रूम से रियल-टाइम मॉनिटर किया जा सकता है। उन्नत तकनीकों से सुसज्जित यह कंट्रोल रूम पुलिस प्रशासन को त्वरित, प्रभावी और सटीक कार्रवाई करने में सहायक सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि यह प्रणाली केवल निगरानी तक सीमित नहीं, बल्कि यह शहर की कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया को भी सुदृढ़ बनाएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग सुशासन की रीढ़ बनेगा।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, बिलासपुर संभागायुक्त सुनील जैन, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर कुन्दन कुमार, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुंगेली जिले के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में बसे ग्राम बिजराकछार में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

सुशासन तिहार के समाधान शिविर में उमड़ा जनसैलाब

मुख्यमंत्री ने डिंडोरी में नए कॉलेज की स्थापना, खुड़िया में पीएचसी का उन्नयन और लोरमी में छात्रावास के निर्माण की घोषणा की

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तीसरे चरण में मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के सुदूर और दुर्गम ग्राम बिजराकछार में आयोजित समाधान शिविर में पहुँचे। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे इस इलाके में पहली बार मुख्यमंत्री का आगमन होते ही ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह दिखा। यह इलाका आदिवासी और बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल है और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ महतारी एवं सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं और किसानों ने पारंपरिक खुमरी के साथ मुख्यमंत्री का गजमाला से अभिनंदन किया।

समाधान शिविर में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने समाधान शिविर में आत्मीयता के साथ ग्रामीणों से मुलाकात की और जनसमस्याओं को सुना। उन्होंने डिंडोरी में नए कॉलेज की स्थापना, खुड़िया में पीएचसी का उन्नयन एवं लोरमी में छात्रावास के निर्माण की ऐतिहासिक घोषणाएँ कीं।

सुशासन तिहार के तृतीय चरण अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिजराकछार, बोईरहा, खुड़िया, महामाई, निवासखार, सुरही, कटामी, लमनी, छपरवा, अचानकमार, दरवाजा, कारीडोंगरी, डोंगरीगढ़, झिरिया क्लस्टर के रूप में शामिल की गई थीं। मुख्यमंत्री ने क्लस्टर की 14 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों से सीधा संवाद कर शासन की योजनाओं की जानकारी ली और उनकी समस्याएं सुनीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने समाधान शिविर में हितग्राहियों को सामग्री वितरण कर लाभान्वित किया। उन्होंने 5 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 5 को राशन कार्ड, नोनी सुरक्षा योजना के 20 हितग्राहियों को बॉन्ड पत्र, सहकारिता विभाग के अंतर्गत 6 हितग्राहियों को 5 लाख 55 हजार रुपये का चेक, 33 हितग्राहियों को पीएम आवास की चाबी और स्वीकृत पत्र, महिला स्व सहायता समूहों को चक्रीय निधि और 3 हितग्राहियों को लखपति दीदी प्रमाण पत्र, मनरेगा के तहत 23 हितग्राहियों को जॉब कार्ड, तेंदूपत्ता संग्रहण परिवार की मेधावी विद्यार्थी को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इस अवसर पर वन विभाग की ओर से अचानकमार जंगल सफारी के लिए गांव की महिला स्व-सहायता समूह को सफारी गाड़ी की चाबी भी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार को लगभग डेढ़ वर्ष हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई अधिकांश गारंटियों को पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 13 दिसंबर को हुई पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख परिवारों को आवास की स्वीकृति दी गई। उन्होंने कहा कि 15 मई तक चल रहे आवास सर्वे में जिन लोगों को अभी तक आवास नहीं मिला है, उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है और एकमुश्त राशि उनके खातों में स्थानांतरित की जा रही है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जिन माताओं के नाम अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। इस योजना से लाभ प्राप्त कर माताएं सुकन्या योजना में धनराशि जमा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता की खरीदी 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से की जा रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ दर्शन कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। 5 लाख 60 हजार से अधिक भूमिहीन मजदूरों को किसान सम्मान योजना का लाभ दिया गया है। सरकार भ्रष्टाचार की संभावनाओं को नवाचार और तकनीक के माध्यम से समाप्त कर रही है तथा सभी कार्यों को ऑनलाइन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की एक-एक गारंटी को धरातल पर उतारने का कार्य पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से कर रहे हैं। हमारी सरकार जनता से किए गए हर वादे को गंभीरता से लेते हुए उसे पूरा करने में जुटी है। आज मुझे एक सांसद के रूप में आप सभी की सेवा करने का गौरव प्राप्त हो रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले हमने वादा किया था कि सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासहीन परिवारों को घर उपलब्ध कराएंगे। हमारी सरकार ने इस वादे को प्राथमिकता दी और सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सबसे पहले प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी। हमारा संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी गरीब भूखा न रहे। इसी दिशा में हर ज़रूरतमंद को नियमित रूप से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है, चाहे वह वनांचल में हो या दूरस्थ अंचलों में। आज हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, और सभी को स्वच्छ पीने का जल सुनिश्चित कराया जा रहा है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से हम माताओं और बहनों का सम्मान कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत उन्हें हर माह एक-एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उनका आत्मबल और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों में वृद्धि हो रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज इस सुदूर वनांचल क्षेत्र बिजराकछार में पधारे हैं। वे सभी महातारियों को 1,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का बेटा, आदिवासी समाज के बीच स्नेह और दुलार लेकर स्वयं आप सभी से मिलने आया है। उन्होंने कहा कि अचानकमार क्षेत्र बैगा आदिवासी समाज का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पहले कई समस्याएँ रही हैं।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950